



Jacqueline Fernandez
Felicitated At...

SHARE	
सेसेक्स	: 82,755.51
निफ्टी	: 25,244.75

SARAFSA	
सोना	: 9,250
चांदी	: 119.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

ईरान ने माना- हमारे परमाणु ठिकानों को पहुंचा नुकसान

NEW DELHI : ईरान ने मान लिया है कि 22 जून को अमेरिकी हमलों से उसके परमाणु ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने बुधवार को इसकी पुष्टि की है। अल जजीरा से बात करते हुए बाघई ने कहा कि अमेरिकी बस्टर बमों के हमले असरदार थे और उससे परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि, बाघई ने नुकसान की डिटेल जानकारी नहीं दी। दूसरी तरफ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नीदरलैंड में नाटो समिट में मीडिया से कहा कि ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के कारण 12 दिनों तक चली ईरान-इजरायल जंग रुकी। उन्होंने कहा, '12 दिनों के दौरान ईरान नर्क से गुजरा, जिसके कारण उसे परमाणु हथियार बनाने की इच्छा छोड़नी पड़ी। अगर ईरान ने फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो हम फिर हमला करेंगे।' अमेरिकी मीडिया हाउस सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि अमेरिकी हमलों से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ है। बस कुछ महीनों के लिए पिछड़ गया है।

इजरायल से लौटे 224 भारतीय नागरिक

NEW DELHI : बुधवार सुबह ऑपरेशन सिंधु के तहत 224 भारतीय नागरिक इजरायल से भारत लौटे। ईरान- इजरायल के तनाव के बीच दोनों देशों से अब तक 3394 भारतीयों को भारत लाया जा चुका है। इससे पहले 24 जून की रात 12.01 बजे 282 भारतीयों को लेकर एक फ्लाइट मशहद से दिल्ली पहुंची थी। उधर, भारतीय दूतावास ने मंगलवार देर रात बताया था कि ईरान और इजरायल के बीच सैन्य संघर्ष के दौरान शुरू किए गए भारतीयों को निकालने के अभियान को बंद कर रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया है। दूतावास ने इवैवएएशन (लोगों को निकालने) के लिए नए नामों को रजिस्टर करने के लिए खोली गई डेस्क को बंद कर दिया।

हल्द्वानी में उफनाती नहर में गिरी कार, चार की मौत

HALDWANI : तेज बरसात के बीच उफनाती नहर में एक कार गिरने से चार जिनगीयां एक पल में खत्म हो गईं। बुधवार सुबह फायर ब्रिगेड दफ्तर के पीछे बहने वाली सिंचाई नहर में एक कार अनियंत्रित होकर गिर गई। कार सवार एक बच्चे समेत चार लोगों की मौत हो गई है, जबकि तीन अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार उधमसिंहनगर जिले के फिक्खा के रहने वाले यह लोग कार से कहीं जा रहे थे। सुबह तेज बारिश के बीचउनकी कार अनियंत्रित होकर सिंचाई नहर में गिर गई। नहर में गिरने के दौरान कार उलटी हो गई और बहकर पुलिया के नीचे फंस गई। जिसके कारण कार के अंदर पानी घुस गया और लोग इसमें फंस गए। इससे कार में बैठे लोगों को सभलने का मौका ही नहीं मिला।

पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में झारखंड को मिली बड़ी सौगात झरिया संशोधित मास्टर प्लान के लिए 5940 करोड़ रुपये मंजूर, 100 वर्षों से जल रहा शहर

PHOTON NEWS RANCHI :

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में झारखंड के लिए बड़ी सौगात दी गई। केंद्रीय कैबिनेट ने झारखंड के धनबाद जिले के बहुत पुराने मुंदे पर स्वीकृति प्रदान कर दी। झरिया भूमिगत (अंडरग्राउंड) आग के लिए संशोधित मास्टर प्लान के लिए 5940 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल गई। कैबिनेट में पारित प्रस्ताव की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। जमीन के अंदर कोयले में लगी आग के कारण झरिया शहर पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से जल रहा है। गौरतलब है कि आग प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए वर्ष 2009 में झरिया मास्टर प्लान बना था।

शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा पर खाना, रचा नया इतिहास आज स्पेस में होगी लैंडिंग



NEW DELHI @ PTI :

बुधवार को भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने एक्सिओम स्पेस द्वारा संचालित वाणिज्यिक मिशन के तहत तीन अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) की यात्रा के लिए रवाना होकर इतिहास रच दिया। रूसी अंतरिक्ष यान के जरिये भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा के 41 साल बाद किसी भारतीय की यह यात्रा हो रही है। स्पेसएक्स के फाल्कन-9 रॉकेट ने दोपहर 12 बजकर एक मिनट पर एक्सिओम मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के लेकर फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से आईएसएस के लिए उड़ान भरी, जिसका दुनिया भर के लोगों ने स्वागत किया। शुक्ला के माता-पिता लखनऊ स्थित 'सिटी मॉन्टेसरी स्कूल' में इस ऐतिहासिक उड़ान के गवाह बने। इसी स्कूल से शुक्ला ने पढ़ाई की है। प्रक्षेपण के 10 मिनट बाद अंतरिक्ष यात्रियों ने धरती का चक्कर काटना शुरू कर दिया, जिसके बाद ड्रैगन अंतरिक्षयान के धरती से ऊपर 200 किलोमीटर



ग्रुप कैप्टन का स्पेसक्राफ्ट से आया पहला संदेश- मेरे कंधे पे है मेरा तिरंगा...

प्रक्षेपण के 10 मिनट बाद अंतरिक्ष यात्रियों ने शुरू कर दिया धरती का चक्कर काटना

शुक्ला के माता-पिता लखनऊ स्थित 'सिटी मॉन्टेसरी स्कूल' में बने इस ऐतिहासिक उड़ान के गवाह

की ऊंचाई पर कक्षा शुक्ला ने अपने संदेश में कहा, नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। कमाल की सवारी थी। मेरे साथ मेरे कंधे पे मेरा तिरंगा है।

बेहतर संभावना पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने हर स्तर पर किए प्रयास

देश की चक्रवात चेतावनी प्रणाली में लगातार देखा जा रहा सुधार

PHOTON NEWS @ RESEARCH DESK :

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 11 साल पूरे होने के बाद विविध क्षेत्रों में उपलब्धियों का आकलन कई स्तरों पर जारी है। यह काम सरकारी स्तर से लेकर पार्टी के संगठन के साथ अन्य निजी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। विज्ञान, तकनीक, कृषि, सामाजिक कल्याण और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि मौसम विज्ञान के क्षेत्र में भी उपलब्धियों का खाका प्रशंसीय दिख रहा है। यह महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है कि पिछले 11 वर्षों में देश में चक्रवात चेतावनी प्रणाली में काफी हद तक सुधार हुआ है और यह सटीक बनने की ओर अग्रसर है। चंद दिन पहले पुष्पेश्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन ने बताया है कि पिछले एक दशक में चक्रवात चेतावनी प्रणाली में अपेक्षित सटीकता आई है। 48 घंटों के अंदर भूस्थूलिक के पूर्वानुमान में 65 प्रतिशत और भारी बारिश, कोहरा और लू जैसी अन्य गंभीर मौसम की घटनाओं में 40 प्रतिशत तक सुधार हुआ है।

● मानसून के पूर्वानुमान में आए बदलावों के कारणों का समझाया गया वैज्ञानिक आधार

● राष्ट्रीय मानसून मिशन के तहत बनाया गया सांख्यिकीय से मौलिकी आधारित मॉडल

● अनुसंधान के बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी में निरंतर निवेश से सुधरा सिस्टम

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन ने विस्तार से दी जानकारी

पिछले साल शुरू किया गया था मिशन मौसम

विभागिय सचिव ने 2014 से 2025 तक मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों को बताया और कहा, ये सुधार पिछले एक दशक में अनुसंधान के बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी में निरंतर

निवेश का परिणाम है। सितंबर 2024 में सरकार ने भारत को मौसम के लिए तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट बनाने के लिए एक राष्ट्रीय पहल मिशन मौसम भी शुरू की।



महासागर विज्ञान और मानवयुक्त पनडुब्बी

रविचंद्रन ने बताया कि महासागर विज्ञान में डीप ओशन मिशन ने मत्स्य-6000 के सफल गीले बंदरगाह परीक्षणों के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जो भारत की मानवयुक्त पनडुब्बी है। यह समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे तक पहुंचने में सक्षम है। इससे गहरे समुद्र में अन्वेषण और समुद्री संसाधनों के सतत निष्कर्षण का मार्ग प्रशस्त होगा। रविचंद्रन का कहना है कि हमने हिंद

महासागर में दो सक्रिय और दो निष्क्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट भी खोजे हैं। जैव विविधता सर्वेक्षणों में 23 नई प्रजातियों की पहचान की है, जिससे महासागर विज्ञान में भारत की स्थिति मजबूत हुई है। मंत्रालय ने भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) से अनुमानित 9.2 लाख टीडब्ल्यूएच वार्षिक अक्षय ऊर्जा क्षमता का आकलन करने के लिए एक एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस भी जारी किया है।

पुनर्वासित परिवारों के लिए बड़ी राहत

संशोधित मास्टर प्लान में आग से प्रभावित क्षेत्रों से पुनर्वासित किए जा रहे परिवारों के लिए आजीविका सुजन पर जोर दिया गया है। इससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। इसके तहत कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे। पुनर्वास वाले परिवारों की आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए आय-सुजन के अवसर भी पैदा किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने अगस्त 2009 में धनबाद जिले में आग, भूस्खलन और पुनर्वास से निपटने के लिए झरिया मास्टर प्लान को मंजूरी दी थी। इसकी कार्यान्वयन अवधि 10 वर्ष और कार्यान्वयन-पूर्व अवधि दो वर्ष रखी गई थी।



एक लाख रुपये का आजीविका अनुदान

7000 करोड़ से अधिक का था पिछला प्लान

12 अगस्त 2009 को तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने 7112.11 करोड़ रुपये के बजट के साथ झरिया मास्टर प्लान को मंजूरी दी थी, ताकि अग्नि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास सहित आग और भू-धंसान से जुड़ी समस्याओं का निवारण किया जा सके। आग से निबटने की पूरी जिम्मेदारी बीसीसीएल की थी, जबकि कोलकमियों को पुनर्वासित करने की जिम्मेदारी बीसीसीएल और गैर बीसीसीएल कमियों के

मंत्री ने बताया कि संशोधित जेएमपी योजना में पुनर्वासित परिवारों की स्थायी आजीविका के साधन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पुनर्वासित परिवारों की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए विशेष कौशल विकास और रोजगार परक उपाय किए जाएंगे। एक लाख रुपये का आजीविका अनुदान और वैध भू-स्वामित्व धारक (एलटीएच) परिवारों और अपजीकृत भू-धारक (नॉन-एलटीएच) परिवारों- दोनों को तीन लाख रुपये तक संस्थागत ऋण सहायता दी जाएगी।

पुनर्वासित करने की जिम्मेदारी झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (जेआरडीए) की है। बता दें कि जमीन के अंदर कोयले में लगी आग के कारण झरिया शहर पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से जल रहा है। राष्ट्रीयकरण के वक्त झरिया कोयलांचल के करीब 17.32 स्क्वायर किलोमीटर में आग का दायरा फैला हुआ था, लेकिन यह करीब 1.53 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में सिमट चुका है।

उत्पाद विभाग ने वित्त विभाग से मांगे ऑडिटर

RANCHI : उत्पाद विभाग ने शराब दुकानों को अपने कब्जे में लेने के लिए वित्त विभाग से ऑडिटर्स की मांग की है। जुलाई से राज्य में नयी उत्पाद नीति लागू की जानी है। नयी नीति में दुकानों की नीलामी का प्रावधान है। फिलहाल इन दुकानों को प्लेसमेंट एजेंसियों के सहारे झारखंड विवेकजेन कॉर्पोरेशन द्वारा चलाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में लागू उत्पाद नीति में राज्य सरकार द्वारा ही खुदरा शराब दुकानों के माध्यम से शराब बेचने का प्रावधान है। इस प्रावधान के आलोक में राज्य विवेकजेन कॉर्पोरेशन द्वारा प्लेसमेंट एजेंसियों के सहारे खुदरा शराब दुकानों के माध्यम से शराब की बिक्री की जाती है। अलग-अलग प्लेसमेंट एजेंसियों को 1453 खुदरा शराब दुकानों को चलाने की जिम्मेदारी दी गयी है। इन प्लेसमेंट एजेंसियों ने शराब की बिक्री से मिली पूरी रकम कॉर्पोरेशन के खाते में जमा नहीं की है। इन एजेंसियों पर करीब 100 करोड़ रुपये के बकायों का अनुमान है।

सूझबूझ से बाघ को कमरे में बंद कर स्थानीय पुलिस व वन विभाग को दी गई जानकारी रांची के सिल्ली में ग्रामीण के घर में घुसा बाघ, मचा हड़कंप, किया गया रेस्क्यू

PHOTON NEWS RANCHI :

रांची जिले के सिल्ली-मुरीओपी क्षेत्र के मारदू गांव में एक ग्रामीण पुरंदर के घर में बाघ के घुस जाने की खबर से पूरे गांव में हड़कंप गया। हालांकि पुरंदर ने सूझबूझ से बाघ को एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस और वन विभाग को दी गई। जानकारी के अनुसार बुधवार को अहले सुबह 4:30 बजे पूरन चंद्र महतो की पुत्री सनिका कुमारी बकरी बांधने अपने घर से बाहर निकली थी, उसी समय एक बाघ कमरे में घुस गया और छिप कर बैठ गया। उसने अंदर कमरे में

दहशत में आया पूरा गांव, प्रशासन ने लागू की निषेधाज्ञा

पिंजरे में कैद

बाघ के कमरे के अंदर घुसते ही लोगों ने बाहर में लगे लोहे के दरवाजे को बंद कर दिया। काफी मशक्कत के बाद आधिकारिक वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो गया। काफी जद्दोजहद के बाद बाघ वन विभाग के पिंजरे में कैद कर लिया गया। इसके लिए पलामू टाइगर रिजर्व की टीम बुलाई गई थी।



रेस्क्यू के बाद पिंजरे के अंदर कैद बाघ।

सो रहे पिता को इसकी सूचना दी और हल्ला करना शुरू किया। पिता ने हल्ला करने से मना करते हुए

अंदर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, मगर अंदर कमरे की छिड़की खुली थी, जिससे बाघ अंदर कमरे

जूटी लोगों की भीड़

खबर फैलते ही आसपास से ग्रामीण काफी संख्या में जुट गए। सूचना पाकर प्रमुख जितेंद्र बड़ाइक, गांव के मुखिया वार्ड सदस्य, वन विभाग के वनरक्षी एवं ओपी पुलिस भी घटना स्थल पहुंची। देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी आपस में चर्चा कर रहे थे कि आखिर कौन सा जानवर हो सकता है। लोग इस बात को लेकर आश्चर्य नहीं थे कि जानवर बाघ ही है।

में प्रवेश कर गया। सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर लिया।

प्रधानमंत्री ने आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में शामिल योद्धाओं को किया सलाम



AGENCY NEW DELHI :

देश में साल 1975 में थोपे गए आपातकाल की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 'सविधान हत्या दिवस' पर इस काले कालखंड की लड़ाई में शामिल हर योद्धा को सलाम किया है। उन्होंने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर लिखा, हम अपने संविधान में निहित सिद्धांतों को मजबूत करने तथा विकसित भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी

- पीएम मोदी ने 'सविधान हत्या दिवस' के संबंध में 'एक्स' पर किए कई पोस्ट
- भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा करने और उसके आदर्शों को बनाए रखने पर दिया जोर

वोहराते हैं। हम प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएं तथा गरीबों और वंचितों के सपनों को पूरा करें।

आरएसएस का था युवा प्रचारक

पीएम ने लिखा, आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक, आपातकाल लागू होने के पचास साल पूरे हो गए हैं। भारत के लोग इस दिन को सविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन, भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया और कई

राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस समय सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। प्रधानमंत्री ने तब के क्रूर कालखंड याद करते हुए लिखा, जब आपातकाल लगाया गया था, तब मैं आरएसएस का युवा प्रचारक था। आपातकाल विरोधी आंदोलन मेरे लिए सीखने का एक अनुभव था।

टोस पहल की जाए। इसके पहले भी कई बार ऐसा मामला सामने आया है, जब प्रवासी मजदूर पैसे कमाने के लिए विदेश चले गए और वहां जाने के बाद उनका शोषण किया गया।

BRIEF NEWS

भारत-नेपाल बॉर्डर पर मैत्री पुल के पास मिला हैंड ग्रेनेड

CHAMPARAN : भारत-नेपाल सीमा के रक्सौल बार्डर पर बहनेवाली सरिसवा नदी पर बने मैत्री पुल के नीचे से हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप व्याप्त है। मिली जानकारी के अनुसार सरिसवा नदी में नहा रहे बच्चों को हैंड ग्रेनेड मिला,जिसे बच्चे खिलौना समझ कर हाथ में लेकर घूम रहे थे। इसी दौरान एसएसबी जवानो की नजर उस पर पड़ी तो हैंड ग्रेनेड को अपने कब्जे में ले लिया। एसएसबी के अधिकारियों के अनुसार हैंड ग्रेनेड मिलने के सरिसवा नदी सहित आसपास के क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है,ताकि कहीं और ग्रेनेड या हथियार तो नदी में तो नहीं फेका गया है।

शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम पर्व संपन्न कराने को लेकर हुई बैठक

ARARIA : फारबिसगंज जुम्मन चौक स्थित मुहर्रम कमेटी के प्रधान महासचिव मो.वाहिद अंसारी के आवास पर बुधवार को शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम पर्व को संपन्न कराने को लेकर मुहर्रम कमेटी की बैठक अध्यक्ष दिलशाद अहमद की अध्यक्षता में हुई। बैठक में शांतिपूर्ण ताजिया जुलूस के साथ अखाड़ों और उसके लिए लाइसेंस के साथ नमाज,इबादत और धार्मिक आयोजनों को लेकर गहनतापूर्वक विचार विमर्श किया गया। ताजिया जुलूस को लेकर बिजली के तार, गड़्डे वाली सड़क की मरम्मत, पेड़ की टहनियों की छांटई जैसे प्रशासनिक कवायद और गुहार लगाने पर चर्चा की गई।

चार माह से बंद था मध्याह्न भोजन, डीएम के निर्देश पर देबारा शुरू हुआ संचालन

PURNIA : पूर्णिया जिलाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित एक समीक्षात्मक बैठक के दौरान यह जानकारी सामने आई कि बनमनखी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय शर्मा टोल, ब्रिशनपुर दत्त में विगत लगभग चार माह से मध्याह्न भोजन योजना का संचालन ठप पड़ा हुआ है। इस गंभीर लापरवाही को संज्ञान में लेते हुए डीएम ने मध्याह्न भोजन योजना के प्रभारी पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी बनमनखी को निर्देशित किया कि अविलंब विद्यालय में एमडीएम योजना का संचालन सुनिश्चित कराया जाए। डीएम के निर्देश के क्रम में एसडीओ बनमनखी द्वारा उक्त विद्यालय का निरीक्षण किया गया।

नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू

CHAMPARAN : जिले के पीपराकोटी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में वर्ग छ में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। आवेदन 29 जुलाई तक दिया जा सकता है। जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण ने बताया कि पीपराकोटी स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा छ: में 80 सीटों पर प्रवेश के लिए पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है।

बिहार में पूरी तरह छाया मानसून, अगले 6 दिनों तक होगी बारिश

AGENCY PATNA : बिहार में मानसून पूरी तरह से छा गया है। दक्षिण-पश्चिम मानसून के सक्रिय होने से राज्य के ज्यादातर जिलों में हर दिन बारिश हो रही है। मंगलवार को पटना और उसके आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 6 दिनों तक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। कुछ जगहों पर मध्यम तो कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। किशनगंज और पश्चिम चंपारण जिलों के लिए बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

गरज के साथ वज्रपात का येलो अलर्ट आईएमडी ने किया जारी



प्रतीकात्मक फोटो

मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया अपडेट

पटना मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि अगले 6 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश जारी रहेगी। इस दौरान कुछ जगहों पर मध्यम तो कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं, किशनगंज और पश्चिम चंपारण जिलों के लिए बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने इस दौरान लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। खासकर खुले इलाकों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने और बिना छत के खड़े रहने से बचने के लिए कहा गया है।

किशनगंज में सबसे अधिक बारिश

पिछले 24 घंटों में किशनगंज के गलग्रिलिया इलाके में सबसे ज्यादा 120.4 मिमी बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा गया, समस्तीपुर, अररिया, भागलपुर, मधुबनी, वैशाली, नालंदा, पूर्वी चंपारण, रोहतास और दरभंगा समेत कई जिलों में भी बारिश हुई है।

लोगों से सतर्क रहने की अपील

पटना आईएमडी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग का कहा है कि खुले में मोबाइल इस्तेमाल करने से बचे और बारिश के दौरान खुले स्थानों पर जाने और रहने से बचे। विभाग का कहना है कि बारिश के मौसम में बिजली गिरने का खतरा सबसे अधिक होता। मौसम विभाग ने किशनगंज और पश्चिम चंपारण के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है।

गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए की कार्रवाई

नवादा में 9 साइबर अपराधी गिरफ्तार, कई सामान बरामद

AGENCY NAVADA : जिले में वारिसलीगंज पुलिस ने बुधवार को थाना क्षेत्र के चकवाय पंचायत स्थित मीरविहा गांव से नौ साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान मीरविहा गांव निवासी सतेन्द्र प्रसाद के पुत्र सुधांशु पटेल, विजय पासवान के पुत्र विक्रमी कुमार, स्वर्गीय अर्जुन राम के पुत्र राजेश कुमार, झारिका ठाकुर के पुत्र सुधीर कुमार, रामवृक्ष पासवान के पुत्र गौतम कुमार, स्वर्गीय प्रेमन पंडित के पुत्र अरविन्द पंडित, अनिल मिस्त्री के पुत्र मंदू कुमार, राजेन्द्र पंडित के पुत्र सुरज कुमार एवं झारखंड राज्य के बोकारो जिला स्थित वेरमो निवासी जगदीश शर्मा के पुत्र संतोष कुमार के रूप में की गई। बुधवार को थाना परिसर में पकरीबरावां एसडीपीओ महेश कुमार चौधरी ने प्रेसवार्ता कर बताया कि पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर पुलिस की एक टीम बनाई गई। थेन के बाघी गांव में छापेमारी की गई.उक्त छापेमारी में पुलिस ने कुल नौ साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस को देखते ही दर्जन भर से ज्यादा साइबर अपराधी फरार होने में सफल रहा। जबकि गिरफ्तारी स्थल से



जानकारी देते एसडीपीओ महेश कुमार चौधरी व अन्य

पूर्वी चंपारण में मिले शव की हुई पहचान, पिता निकला पुत्री का हत्यारा

EAST CHAMPARAN : जिले के तुरकोलिया थाना क्षेत्र स्थित पुलवाघाट बनीती नदी के किनारे 20 जून को मिले सड़े गले शव की पहचान पुलिस ने कर ली है। उक्त शव की पहचान तुरकोलिया नयका टोला गांव के मनोज सिंह की पुत्री बान्दी कुमारी (16वर्ष) के रूप में हुई है। इसकी जानकारी देते एससीपी सदर-1 शिवम धाकड़ ने बताया कि बान्दी की हत्या उसके पिता मनोज ने ही किया था। हत्या के बाद साक्ष्य को छुपाने के लिए उसने गद्दा खोदकर शव को गाड़ दिया था। पुत्री के प्रेम-प्रसंग के कारण पिता ने उक्त कदम उठाया। पुलिस ने मामले में हत्याएं

पिता को गिरफ्तार कर लिया है। मनोज हरसिद्धि थाना क्षेत्र के धवही गांव का रहने वाला है। वर्तमान में वह तुरकोलिया के नयका टोला में घर बनाकर रह रहा था। एससीपी ने बताया कि 20 जून को एक अज्ञात शव पुलवाघाट के पास मक्के के खेत से मिला। तुरकोलिया थाना ने मजिस्ट्रेट और एफएसएल टीम की उपस्थिति में सड़े गले शव के अंशोध को गद्दे से बरामद किया। अनुसंधान के क्रम में बेतिया से डॉन सखायड की टीम भी मंगाई गई थी। इस दौरान सड़े गले शव के पास से एक पीले रंग का फ्रॉक भी मिला था। जिसपर कढ़ाई की गई थी और उस टेलर का टैग भी लगी

थी। अज्ञात शव के सड़े गले होने के कारण एफएमटी विभाग एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में डीएनए का प्रोफाइलिंग की गई है। फ्रॉक में लगे टैग से टेलर की पहचान कर टेलरिंग मास्टर से भी पुष्टाछ की गई, साथ ही वैज्ञानिक साक्ष्य एवं सूचना के आधार पर शव के संबंध में जानकारी प्राप्त हुआ। जिसके बाद पुलिस ने इस क्लाईड केस को सुलझा लिया है। पुत्री की हत्या करने वाले आरोपी पिता मनोज सिंह ने अपना गुनाह कबूल करते बताया कि बैटी के प्रेम प्रसंग से तंग आ गया था, लोक लाज के डर से उसने बैटी की हत्या कर शव को गद्दा खोद कर छुपा दिया था।

पुलिस ने कुल 11 एण्ड्रॉयड मोबाइल, एक कौनडे मोबाइल, एक डेटा कॉपी तथा एक कस्टमर सीट जब्त किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार साइबर

अपराधी रिलायंस फाइनेंस व अन्य कंपनियों से लोन दिलाने के नाम पर भोले-भाले लोगों को ठगी का शिकार बनाता है। एसडीपीओ ने बताया कि

जब्त मोबाइल में लगा सिम कार्ड का नम्बर फर्जी पाया गया। दो मोबाइल नम्बर से साइबर से संबंधित पुलिस के पास ठगी का शिकायत दर्ज है।

बढ़ते अपराध व प्रशासनिक विफलता के खिलाफ राजद कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

AGENCY ARARIA : अररिया समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर राजद की ओर से बुधवार को बढ़ते अपराध और प्रशासनिक विफलता के खिलाफ जिलाध्यक्ष मनीष यादव की अध्यक्षता में एकदिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया।जिसमें बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और बिहार सरकार पर अपराध पर रोक लगाने में असफल करार दिया।अपराध मुक्त बिहार के मांग को लेकर राजद कार्यकर्ताओं ने जमकर बिहार सरकार को अपने निशाने पर लिया। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार में अपराध बेकायम हो चुका है।सत्ता संपोषित अपराधियों के द्वारा विपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है।



फारबिसगंज में अंजार अंसारी हत्याकांड पर वक्ताओं ने निष्पक्ष जांच करते हुए आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की।वक्ताओं ने बढ़ते अपराध को लेकर कहा कि भाजपा और जदयू के नेताओं के लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के काल को जंगलराज की संज्ञा देते हैं,जबकि वर्तमान समय में बिहार महाजंगलराज वाली स्थिति से

गुजर रहा है।दिनदहाड़े लूटकांड और हत्या का दौर चल रहा है और पुलिस प्रशासन उस पर अवैध रूप से विद्युत ऊर्जा चोरी करने को लेकर नौ लाख रुपये जिसमें विद्युत बकाया सहित जुमाना लगायी गयी है। उक्त उपभोक्ताओं के द्वारा मीटर बाईपास करने के कारण वास्तविक मान पठन अवरूद्ध हो रहा था तथा विभाग के राजस्व की क्षति हो रही थी।

अवैध रूप से विद्युत चोरी करने के आरोप में 52 पर प्राथमिकी दर्ज

SAHARSA : जिले में अवैध रूप से विद्युत ऊर्जा चोरी की घटना की रोकथाम को लेकर चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत सभी कनीय विद्युत अभियंता के नेतृत्व मे एक जांच दल का गठन कर 52 पर प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है। वहीं बकाया नहीं जमा नहीं करने के कारण 1575 लोगों का कनेक्शन काटा गया। कनीय विद्युत अभियंता के द्वारा बताया गया की मीटर से पहले मुख्य सर्विस तार मे कटिंग कर एवं एक अतिरिक्त तार जोड़कर मीटर बाईपास करते हुए अवैध रूप से विद्युत ऊर्जा चोरी करने को लेकर नौ लाख रुपये जिसमें विद्युत बकाया सहित जुमाना लगायी गयी है। उक्त उपभोक्ताओं के द्वारा मीटर बाईपास करने के कारण वास्तविक मान पठन अवरूद्ध हो रहा था तथा विभाग के राजस्व की क्षति हो रही थी।

आपातकाल का कलंक कांग्रेस का काला कारनामा : प्रवीण कुमार

AGENCY ARARIA : लोकतंत्र पर प्रहार करने का दुःखद दिन 25 जून 1975 को देश के माथे पर आपातकाल का कलंक लगाने वाली कांग्रेस के काले कारनामे को देश कभी ना भूलेगा,न देश कभी कांग्रेस को इसके लिए माफ करेगा। उक्त बातें भाजपा विधानसभा प्रभारी प्रवीण कुमार ने आपातकाल के 50वाँ बरसी पर कहीं। आपातकाल देश के लिए अपराधी के विरुद्ध पुलिस छापेमारी से कार्यकर्ताओं को अवतार कराने हेतु बुधवार को नगर अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद मिंटू की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए विधानसभा प्रभारी कुमार ने कहा कि स्वतंत्र भारत मे 25 जून 1975 के अद्वारात्रि को कांग्रेस द्वारा देश पर थोपे गये



शर्मनाक आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण सहित अरुल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, राजनारायण, नानाजी देशमुख कपूरी ठाकुर जैसे अनेकों प्रमुख नेता सहित 21 महीने के आपात काल के 1 लाख 10 हजार लोगों गिरफ्तार कर प्रेस पर संसर लगा,अखबारों के जुबान पर ताले जड़ दिये गये और देश वासियों

भीषण यातनाएं सहने पर मजबूर कर दिया गया था। कुमार ने सविधान के अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग कर लगाए गए इमरजेंसी के विरुद्ध गम्भीर यातनाएं सह कर भी अपनी आवाज बुलंद करने वाले सत्याग्रहियों सेनानियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा कि एक परिवार की सत्ता के लालच ने संसद को निष्क्रिय बनाकर देश को रातों रात जेल में तब्दील कर दिया।

अपनी शिकायतें लेकर सचिवालय की परिक्रमा न करें शिक्षक : डॉ. सिद्धार्थ

AGENCY ATNA : स्थानांतरण से संबंधित अपनी शिकायतों को लेकर राज्य के विभिन्न जिलों से शिक्षकों की सचिवालय परिक्रमा लगातार जारी है। जिससे शिक्षा विभाग के कामकाज प्रभावित होने लगे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बुधवार को राज्य के सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर उन्हें निर्देश दिया है कि जब जिलों में ही स्थानांतरित शिक्षकों की स्थापना संबंधित समस्याओं के समाधान की व्यवस्था है, तब शिक्षकों का सीधे राज्य मुख्यालय की परिक्रमा करना उचित नहीं है। इससे विभाग में कामकाज के संचालन में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। डॉ. सिद्धार्थ ने जिलाधिकारियों को लिखे अपने पत्र में कहा है कि शिक्षा विभाग का

स्थापना बल दस लाख है। अगर इस बल का आंशिक प्रतिशत भी अपनी समस्याओं को लेकर राज्य मुख्यालय आता है तो यह संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। इससे शिक्षकों को तो समस्या हो ही रही है, साथ ही विभागीय कार्यों के संचालन में भी समस्याएं आ रही हैं। अपनी स्थानांतरण संबंधी समस्याओं को लेकर शिक्षकगण राज्य मुख्यालय में कार्यरत पदाधिकारियों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं। जिससे विभागीय कामकाज में दिक्कतें पैदा होती हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि जिलों के अंदर स्थापना संबंधी समस्याओं को जिलास्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्थापना समिति द्वारा केस टू केस विचार कर यथोचित कार्रवाई की जाती है।

14 वर्षों में 2412 करोड़ खर्च कर छात्राओं की तादाद में हुआ इजाफा, आत्मविश्वास भी बढ़ा

पोशाक योजना बनी बेटियों की ताकत, बदल गई स्कूलों की तस्वीर

AGENCY PATNA : बिहार की बेटियों के लिए शिक्षा अब सिर्फ सपना नहीं, हक बन चुकी है। इसके पीछे एक बड़ी वजह बनी है मुख्यमंत्री पोशाक योजना। जिसने 14 वर्षों में न सिर्फ छात्राओं की संख्या बढ़ाई, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और गरिमा भी दी। 2011 से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक करीब 1 करोड़ 94 लाख 55 हजार 264 छात्राओं को पोशाक के लिए राशि दी जा चुकी है, जिस पर सरकार ने कुल 2412.47 करोड़ रुपये खर्च किए गए। साल 2018-19 में योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई, जिससे छात्राओं की स्कूल में उपस्थिति और



आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। वर्तमान शैक्षणिक

सत्र 2025-26 में एक करोड़ से अधिक छात्राओं को अप्रैल माह

में ही पोशाक की राशि डीबीटी के जरिए भेज दी गई। इसके लिए

सरकार ने 710 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी।

शिक्षा बजट में जबरदस्त वृद्धि

वर्ष 2005 में शिक्षा विभाग का बजट जहां 4400 करोड़ रुपये था, वहीं अब यह बढ़कर 60,000 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। इसमें पोशाक और साइकिल योजना जैसे प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रमुख हैं। राज्य का राजकोषीय घाटा भी 2020-21 के 9.2 फीसद से घटकर 2023-24 में लगभग 3 फीसद पर आ गया है। जिससे स्पष्ट है कि सरकार वित्तीय अनुशासन और शिक्षा निवेश, दोनों में संतुलन बनाए हुए है।

बेटियों की बढ़ी भागीदारी

इन योजनाओं का सीधा असर राज्य की साक्षरता दर, खासकर बालिका शिक्षा में अभूतपूर्व वृद्धि के रूप में सामने आया है। सरकारी और स्वतंत्र रिपोर्टों में यह स्पष्ट हुआ है कि विद्यालयों में लड़कियों की उपस्थिति और नामांकन दर दोनों में उल्लेखनीय उछाल आया है।

कर्नाटक सरकार का फेक न्यूज कानून या विचारों का गला घोटने की साजिश

कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तावित सोशल मीडिया विनियामक प्राधिकरण विधेयक 2025, जिसमें सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने पर सात साल की सजा और दस लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है, भारतीय लोकतंत्र के लिए चिंताजनक संकेत है। यह कानून सतही तौर पर गलत सूचना के विरुद्ध कार्रवाई का प्रयास लगता है, लेकिन इसके गहरे राजनीतिक और वैचारिक निहितार्थ हैं। यह कदम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐतिहासिक प्रवृत्तियों की पुनरावृत्ति के समान है, जिसमें असहमति और आलोचना को कुचलने की नीति रही है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया उपभोक्ता देश है। 2025 तक भारत में लगभग 85 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से 70 करोड़ लोग सोशल मीडिया का नियमित उपयोग करते हैं। वाट्सएप के 53 करोड़, यूट्यूब के 45 करोड़, फेसबुक के 35 करोड़, इंस्टाग्राम के 33 करोड़ और ट्विटर (एक्स) के 2.5 करोड़ से अधिक मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। सोशल मीडिया अब केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि समाचार, सूचना, अभिव्यक्ति, रोजगार और जनआंदोलनों का प्रभावी मंच बन चुका है। इसी डिजिटल शक्ति को नियंत्रित करने की राजनीतिक इच्छा ने इस प्रकार के कठोर विधेयक को जन्म दिया है। इस प्रस्ताव के अनुसार एक छह सदस्यीय प्राधिकरण गलत सूचना की पहचान करेगा और जरूरत समझे तो सामग्री को हटाने, प्रकाशन को रोकने या आर्थिक दंड लगाने का अधिकार रखेगा। इस प्रक्रिया में सरकार समर्थित निकाय को यह निर्णय लेने की खुली छूट मिल जाती है कि कौन सी जानकारी सत्य है और कौन-सी असत्य। जो लोकतांत्रिक विचार प्रक्रिया के विपरीत है। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी जब-जब सत्ता में रही है, उसने असहमति की आवाजों को कुचलने के प्रयास किए हैं। वर्ष 1975 में लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निलंबित कर, प्रेस पर सेंसरशिप लागू की और हजारों विपक्षी नेताओं को बिना सुनवाई जेलों में डाल दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन, अखबारों की प्रतियों को प्रिंट से पहले अनुमोदन के लिए भेजना अनिवार्य कर दिया गया था। यही नहीं, कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान भी इंटरनेट सेंसरशिप को कोशिशें की गईं। आइटी एक्ट की धारा 66ए का दुरुपयोग कर सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर छात्रों और आम नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में श्रेया सिंगल बनाम भारत सरकार के ऐतिहासिक निर्णय में इस धारा को असंवैधानिक घोषित किया। फिर भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें नए रूपों में सेंसरशिप को पुनः लागू करने का प्रयास करती रही हैं। वर्तमान प्रस्तावित कानून में जो सबसे खतरनाक बात है वह यह कि किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट को इस आधार पर फेक न्यूज कारर दिया जा सकता है कि वह किसी समुदाय, जाति, धर्म, महिला या राज्य की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। यह परिभाषा इतनी व्यापक और अस्पष्ट है कि इसका उपयोग किसी भी आलोचक, पत्रकार, राजनीतिक विरोधी या आम नागरिक के विरुद्ध किया जा सकता है। कर्नाटक सरकार पर कुछ आरोप लगे हैं जैसे साम्प्रदायिक तत्वों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण दिया है। वक्फ बोर्ड की शक्तियों और बजट में वृद्धि की है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध हिजाब को समर्थन दिया है, सरकारी पेसे से मददसी में सांप्रदायिक शिक्षा को सुचारू किया है, शांति सम्मेलनों के नाम पर केवल मुस्लिम वक् को वरीयता दी है। विगत दिनों कई जिलों में हनुमान जयंती और रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध या धारा 144 तथा पुलिस द्वारा कड़ी शर्तें लगाई गईं, जिसे पक्षपातपूर्ण बताया गया। श्रीराम सेना, बजरंग दल आदि संगठनों के खिलाफ एफआईआर और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई बढ़ी है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में भी की गई थी। हिंदू मंदिरों की आय का सरकारी नियंत्रण करते हुए मंदिरों की आय का प्रयोग अन्य सेकुलर उद्देश्यों में करना, जबकि अन्य धर्मस्थलों की आय उनके समुदाय के पास ही रहती है। मदिरा प्रबंधन बोर्डों में गैर-सनातन व्यक्तियों की भागीदारी करना। कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तकों से वीर सावरकर, हिंदू महापुरुषों से जुड़ी जानकारी कम करना या हटाना, जबकि मुस्लिम शासकों पर अध्याय जोड़ना गौतमस्की और गौतम्य पर सख्ती के बजाय ऐसे मामलों में सरकार द्वारा समर्थन करना। उक्त कार्यों से यह युक्तियुक्त आशंका हो गई है कि इस कानून का दुरुपयोग हिंदू समाज के विरुद्ध ही बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और विधि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि आइटी एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामलों में दोषसिद्धि दर अत्यंत कम- मात्र 3 से 5 प्रतिशत के बीच है। उदाहरणस्वरूप, वर्ष 2022 में फेक न्यूज, साइबर मानहानि, अफवाह फैलाने आदि के तहत लगभग 8500 मामले दर्ज किए गए, लेकिन केवल 410 मामलों में ही दोष सिद्ध हो सका। ऐसे में इतने कम दोषसिद्धि दर वाले अपराधों के लिए कठोर दंड और उच्च अर्थवर्षा जुर्माना न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। प्रस्तावित कानून में विशेष न्यायालयों की स्थापना और प्राधिकरण को अर्ध-न्यायिक अधिकार देने की बात कही गई है। ये व्यवस्थाएं निष्पक्ष न्याय की अवधारणा को कमजोर करती हैं। जब जांच, प्रमाण और निर्णय- तीनों प्रक्रिया एक ही प्राधिकरण के अधीन हो जाए, तो वह तंत्र सत्ता का औजार बन सकता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस कानून का सबसे अधिक असर उन्हीं वर्गों पर पड़ेगा जो पहले से हाशिये पर हैं- स्वतंत्र पत्रकार, प्रगतिशील विचारक, निष्पक्ष कार्यकर्ता और सामान्य नागरिक को सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर सवाल उठाते हैं। ऐसी स्थिति में यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नहीं, अभिव्यक्ति पर नियंत्रण का औजार बन जाता है। भारत का संविधान अपने अनुच्छेद 19(1)(ए) में प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार देता है। हालांकि इस अधिकार पर कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध संभव हैं, किंतु वे केवल संकुचित, स्पष्ट और न्यूनतम होने चाहिए।



प्रहलाद सबनानी

वर्ष 1914 से वर्ष 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध एवं वर्ष 1939 से वर्ष 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध इसके उदाहरण हैं। इजराइल-ईरान के बीच हाल ही में प्रारंभ हुए युद्ध में अमेरिका भी कूटने की तैयारी करता हुआ दिखाई दिया और अखित खुद भी गया है। यदि संघर्ष विराम नहीं होता तो बहुत संभव है कि ईरान की सहायता के लिए रूस एवं चीन भी इस युद्ध में कूद पड़ें एवं यह युद्ध तृतीय विश्व युद्ध का स्वरूप ले ले। ऐसा कहा जा रहा है कि इजरायल एवं अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन करवाना चाह रहे हैं, ताकि ईरान में उनके हितों को साधने वाली सरकार स्थापित हो सके। वैश्विक स्तर पर आज परिस्थितियां बहुत सहज रूप से नहीं चल रही है। विभिन्न देशों के बीच विश्वास की कमी हो गई है, जिसके चलते छोटे-छोटे मुद्दों को तूल दी जाकर आपस में खटास पैदा करने के प्रयास हो रहे हैं। कुछ देश, दो देशों के बीच, इन मुद्दों को हवा देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे आतंकवाद के मुद्दे को ही लें, यदि ये देश आतंकवाद से स्वयं ग्रसित हैं, तो इनके लिए आतंकवाद बुराई की जड़ है और यदि कोई अन्य देश आतंकवाद को लम्बे समय से झेल रहा है तो इन देशों के लिए आतंकवाद कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। बल्कि, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को प्रोत्साहन दिया जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

रूस-यूक्रेन एवं इजरायल-हमास के बीच युद्ध अभी समाप्त भी नहीं हुआ है और तीसरे मोर्चे इजरायल-ईरान के बीच भी युद्ध शुरू हो गया। गनीमत रही की 24 जून को दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हो गया। गौरतलब है कि इस बीच भारत-पाकिस्तान के बीच भी युद्ध छिड़ गया था, परंतु भारत की बड़े भाई की भूमिका के चलते इस युद्ध को शीघ्रता से समाप्त करने में सफलता मिल गई थी। दो देशों के बीच युद्ध में किसी एक देश का फायदा नहीं होकर बल्कि दोनों ही देशों का नुकसान ही होता है। परंतु, आवेश में आकर कई बार दो बड़े देश भी आपस में टकरा जाते हैं एवं इन दोनों देशों के पक्ष एवं विपक्ष में कुछ देश खड़े हो जाते हैं, जिससे कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि विश्व युद्ध छिड़ जाते हैं। वर्ष 1914 से वर्ष 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध एवं वर्ष 1939 से वर्ष 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध इसके उदाहरण हैं। इजराइल-ईरान के बीच हाल ही में प्रारंभ हुए युद्ध में अमेरिका भी कूटने की तैयारी करता हुआ दिखाई दिया और अंकित खुद भी गया है। यदि संघर्ष विराम नहीं होता तो बहुत संभव है कि ईरान की सहायता के लिए रूस एवं चीन भी इस युद्ध में कूद पड़ें एवं यह युद्ध तृतीय विश्व युद्ध का स्वरूप ले ले। ऐसा कहा जा रहा है कि इजरायल एवं अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन करवाना चाह रहे हैं, ताकि ईरान में उनके हितों को साधने वाली सरकार स्थापित हो सके। वैश्विक स्तर पर आज परिस्थितियां बहुत सहज रूप से नहीं चल रही है। विभिन्न देशों के बीच विश्वास की कमी हो गई है, जिसके चलते छोटे-छोटे मुद्दों को तूल दी जाकर आपस में खटास पैदा करने के प्रयास हो रहे हैं। कुछ देश, दो देशों के बीच, इन मुद्दों को हवा देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे आतंकवाद के मुद्दे को ही लें, यदि ये देश आतंकवाद से स्वयं ग्रसित हैं, तो इनके लिए आतंकवाद बुराई की जड़ है और यदि कोई अन्य देश आतंकवाद को लम्बे समय से झेल रहा है तो इन देशों के लिए आतंकवाद कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। बल्कि, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को प्रोत्साहन दिया जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चौधरी बन रहे कुछ देश अपनी विस्तरवादी नीतियों के चलते कई देशों में अपने हित साधने वाली सरकारों



की स्थापना करना चाह रहे हैं एवं इन देशों में इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित करने के प्रयास कर रहे हैं ताकि ये देश आपस में लड़ाने प्रारम्भ करें। रूस एवं यूक्रेन के बीच युद्ध इसका जीता जाता उदाहरण है। साथ ही, कुछ देशों की कथनी और करनी में पाए जाने वाले फर्क के चलते भी वैश्विक स्तर पर परिस्थितियां बिगड़ रही हैं। चौधरी बन रहे देशों को तो उदाहरण पेश करते हुए अपनी कथनी एवं करनी में फर्क को समाप्त करना ही होगा। अन्यथा वैश्विक स्तर पर परिस्थितियां भयावह स्तर तक पहुंच सकती हैं। चूंकि इजरायल भी आतंकवाद से पीड़ित देश है एवं आतंकवाद की सीमाएं चार मुस्लिम राष्ट्रों से जुड़ी हुई हैं- यथा- उत्तर में लेबनान, दक्षिण पश्चिम में ईजिप्ट (एवं गाजा), पूर्व में जॉर्डन (एवं वेस्ट बैक) एवं उत्तर पूर्व में सीरिया। ईजरायल अत्यधिक आक्रामकता के साथ आतंकवादियों (हमास एवं हूथी आदि संगठनों) से युद्ध करता रहता है। इस्लाम के अनुयायी यहूदियों के कट्टर दुश्मन हैं, इसके चलते भी इजरायल के नागरिकों को आतंकवाद को लंबे समय से झेलना पड़ रहा है। ईरान के बारे में तो कहा जा रहा है कि ईरान स्थित लगभग 60 प्रतिशत मस्जिदों में इबादत के लिए कोई भी व्यक्ति पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि ईरान में एवं ईरान द्वारा पड़ोसी देशों में फैलाए गए आतंकवाद से ईरान के मूल नागरिक अत्यधिक परेशान हैं। महिलाओं पर आतंकवादियों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से स्थानीय नागरिक बहुत दुखी हैं। अतः अब वे अपने पुराने धर्म जोरोस्ट्रीयन को अपनाने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं अथवा इस्लाम धर्म का परित्याग करना चाह रहे हैं।

जोरोस्ट्रीयन, ईरान का मूल धर्म हैं एवं यह अब ईरान के कुछ (बहुत कम) क्षेत्रों में सिमट कर रह गया है। भारत में भी जोरोस्ट्रीयन धर्म को मानने वाले पारसी समुदाय के कुछ नागरिक शांतिपूर्वक रह रहे हैं एवं भारत के आर्थिक विकास में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। वैश्विक स्तर पर निर्मित हो रही उक्त वर्णित परिस्थितियों के बीच भारत की विशेष भूमिका रह सकती है, क्योंकि भारत के इजरायल एवं ईरान दोनों ही देशों के साथ आर्थिक रिश्ते बहुत मजबूत हैं। भारत, ईरान से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता रहा है एवं भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के निर्माण में भारी आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान की है। चाबहार बंदरगाह का संचालन भी ईरान की सरकार के साथ भारतीय इंजीनियरों द्वारा ही किया जा रहा है। भारत और ईरान के बीच प्रतिवर्ष 200 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि का विदेशी व्यापार होता है। दूसरी ओर, इजराइल भारत का रणनीतिक साझेदार है। भारत इजरायल से भारी मात्रा में सुरक्षा उपकरण भी खरीदता है। भारत और इजरायल के बीच प्रतिवर्ष 650 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि का विदेशी व्यापार होता है, इसमें भारत द्वारा इजराइल से आयात किए जाने वाले सुरक्षा उपकरणों की राशि शामिल नहीं है। कुल मिलाकर, भारत के इजराइल एवं ईरान, दोनों देशों के साथ बहुत पुराने व्यापारिक एवं सांस्कृतिक रिश्ते हैं। भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम; सर्वजन हिताय सर्वकृति एवं सर्वे भवतु सुखिनः को अपनाने के भावना पर विश्वास किया जाता है। अतः भारतीय नागरिक सामान्यतः शांत स्वभाव के

होते है एवं पूरे विश्व में ही भ्रातृत्व के भाव का संचार करते हैं। आज चार करोड़ से अधिक भारतीय मूल के नागरिक विभिन्न देशों के आर्थिक विकास में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। इन देशों में होने वाले अपराधों में भारतीय मूल के नागरिकों की संलिप्तता लगभग नहीं के बराबर पाई गई है। इसी कारण के चलते आज विद्यतनाम, जापान, इजराइल, आस्ट्रेलिया एवं सिंगापुर जैसे कई देश भारतीय मूल के नागरिकों को अपने देश में कार्य करने एवं बसाने में सहायता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खाड़ी के देश यथा ओमान, बहरीन, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमीरात आदि में भी लाखों की संख्या में भारतीय मूल के नागरिक निवास कर रहे हैं एवं शांतिप्रिय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुल मिलाकर, विभिन्न देशों में निवासरत भारतीय मूल के नागरिकों का रिकार्ड बहुत ही संतोषजनक पाया जाता है, क्योंकि भारतीयों की मूल प्रकृति ही सनातन हिंदू संस्कारों के अनुरूप पाई जाती है एवं वे किसी भी प्रकार के कर्म में धर्म को जोड़कर ही इसे सम्पन्न करने का प्रयास करते हैं और धर्म के अनुरूप किये गए किसी भी कार्य से किसी का अहित हो ही नहीं सकता। उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में वैश्विक स्तर पर जब चौधरी बन रहे देशों द्वारा अन्य देशों के साथ न्याय नहीं किया जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो ऐसे में भारत को आगे आकर युद्ध में झोंके जा रहे देशों के नागरिकों की मदद करनी चाहिए। भारत की तो वैसे भी नीति ही वसुधैव कुटुम्बकम की है। यदि पूरे विश्व में भाईचारा फैलाना है तो सनातन हिंदू संस्कृति के अनुपालन से ही यह सब सम्भव हो सकता है। उक्त परिस्थितियों के बीच सनातन हिंदू संस्कृति की स्वीकार्यता विभिन्न देशों के नागरिकों की बीच तेजी से बढ़ भी रही है, क्योंकि कई देश अब आतंकवाद से बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं। अतः अब वे किसी तीसरे रास्ते की तलाश में हैं। इन विपरीत परिस्थितियों के बीच उनके पास अब विकल्प केवल सनातन हिंदू संस्कृति के संस्कारों को अपनाने का ही बचता है, जिसके प्रति वे लालायित भी हैं। और फिर, आतंकवाद से यदि छुटकारा पाना है तो इससे लड़ते हुए छुटकारा पाने में तो कुछ देशों को कई प्रकार के बलिदान देने पड़ सकते हैं और यदि सनातन हिंदू संस्कृति के संस्कारों की स्वीकार कर लिया जाता है तो कई देशों के नागरिकों को इस बलिदान से बचाया जा सकता है।

प्राकृतिक तरीके से बरकरार रखें शरीर का हाइड्रेशन

पसिने के कारण शरीर से जरूरी मिनरल्स और पानी तेजी से निकल जाते हैं। इसकी वजह से शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन की दिक्कत हो जाती है। ऐसा गर्मी में अधिक होता है। गर्मी में अपने शरीर को हाइड्रेट करने के लिए ज्यादातर लोग पानी पीते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होता। क्योंकि एक तो पानी बेस्वाद होता है और दूसरे इसमें पर्याप्त मिनरल नहीं होते, जोकि शरीर को भरी दुपहरी ऊर्जावान रख सके। हालांकि कुछ लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए काबोनेटेड ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं, जिनमे केमिकल और आर्टिफीसियल फ्लेवोर्स को मिलाकर एक उन्दा स्वाद तैयार किया जाता है और लोग अपने परिवार और मेहमानों को शौक से काबोनेटेड ड्रिंक्स पिलाते हैं। लेकिन, इन ड्रिंक्स के लगातार उपयोग से शुगर और पेट सहित अन्य अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। गर्मियों के मौसम में शरीर को तरोताजा रखने के लिए अनेक

हेल्दी ड्रिंक्स उपलब्ध हैं, जो शरीर में पानी की कमी दूर करते हैं और आपको अन्दर से मजबूत भी रखते हैं। नारियल पानी प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक पेय है। यह शरीर को हाइड्रेट करता है। इससे आप ऊर्जावान और एक्टिव महसूस करते हैं। यह ना सिर्फ शरीर को ठंडक देता है, बल्कि इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है। इससे ताजगी और ऊर्जा दोनों प्रदान होती है। नारियल पानी पीने से थकान और कमजोरी दूर होती है और यह पाचन क्रिया को भी सुधारता है। नारियल पानी को दिन में किसी भी समय पिया जा सकता है। हालांकि आयुर्वेदार्च्य इसे सुबह खाली पेट पीने की सलाह देते हैं ताकि आपको इसका अधिकतम लाभ मिल सके। नारियल पानी में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी होते हैं। यह स्किन को अंदर से ग्लोइंग बनाने में मददगार हैं। सुबह खाली पेट एक गिलास नारियल पानी पीने से त्वचा हेल्दी और आकर्षक बनती है। नारियल पानी में फाइबर होता

है। यह पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है। रोजाना एक गिलास नारियल पानी पीने से पेट को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है। नारियल पानी में 94 प्रतिशत पानी की मात्रा होती है। यह शरीर को जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति करता है। गर्मियों के महीने में आउटडोर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स आदि के बाद नारियल पानी का सेवन काफी लाभदायक माना जाता है। गर्मियों में पुदीना छछ पीने से पेट शांत रहता है और पाचन क्रिया सही रहती है। यह शरीर को ठंडक और हाइड्रेशन दोनों प्रदान करता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन बी 12 जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ कमजोरी और थकान को भी दूर करते हैं। छछ में इलेक्ट्रोलाइट्स तत्व विद्यमान होते हैं। यह शरीर के वाटर बैलेंस को बनाए रखने में मदद रखते हैं। छछ में दूध और दही के मुकाबले पानी की मात्रा ज्यादा होती है जबकि फैट और कैलोरी की मात्रा

कम होती है। मोनोपौज के बाद जिन महिलाओं का स्वभाव चिड़-चिड़ा हो जाता है। उन्हें निर्मित रूप से एक गिलास छछ का सेवन करना चाहिए। अगर छछ के खट्टे स्वाद से आप परेशान रहते हों तो इसका सेवन हल्के-फुल्के मसाले और काला नमक मिलाकर किया जा सकता है। छछ को दोपहर के खाने के साथ पीना सबसे ज्यादा हितकर माना जाता है। इस समय छछ पीने से ब्लोटिंग, गैस और एसिडिटी से छुटकारा मिलता है। हम अक्सर तला भुना या मसालेदार खाना खाते रहते हैं। इसकी वजह से शरीर के अंदर का तापमान बढ़ जाता है। छछ में प्रोबायोटिक्स तत्व मौजूद होते हैं और रोजाना एक गिलास छछ पीने से इस समस्या से राहत पाई जा सकती है। गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है, लेकिन अनेक लोगों को सादे पानी का स्वाद पसन्द नहीं आता। इसकी वजह से वह पानी पीने से कतराते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं तो फ्लेवर्ड पानी आपके

लिए बेहतर विकल्प है। फलों से तैयार यह पानी आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक हो सकता है। आपको गर्मी से भी बचाएगा और पानी की कमी भी नहीं होने देगा। फ्लेवर्ड पानी बनाने के लिए सादे पानी में ताजे फल, जड़ी बूटियों, सब्जियों और मसालों आदि का स्वाद मिलाकर इसे स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाया जाता है। पानी को फ्लेवर्ड बनाने से उसमें विटामिनस और मिनरल्स की मात्रा भी बढ़ जाती है। इस वजह से हम दिन भर ऊर्जावान रहते हैं। फ्लेवर्ड पानी के कारण हम काबोनेटेड ड्रिंक्स और सोडा आदि के सेवन से बचे रहते हैं। फ्लेवर्ड वॉटर के कई तरह के फल और जड़ी बूटियों के तत्व मिले होने से यह हेल्दी होता है और अच्छे से डिटॉक्स करता है। लेकिन फ्लेवर्ड वॉटर तब हानिकारक भी हो जाता है, अगर वह बाजार का बोतल बंद फ्लेवर्ड वाटर है और उसमें जरूरत से ज्यादा कृत्रिम मिठास और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। फ्लेवर्ड वॉटर बनाने के लिए मटके या सुराही में

इंगूरपुर के लोक में बसा बालिका कालीबाई का बलिदान

यह घटना उन दिनों की है, जब अंग्रेजों ने भारत से जाने की घोषणा कर दी थी और भारत विभाजन की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई थी। लेकिन, अंग्रेज जाते जाते कुछ ऐसा करके जाना चाहते थे कि चर्च की जमाशुट पर कोई अंतर न आए और न उनकी कोई सांस्कृतिक परंपरा प्रभावित हो। इसके लिए उनके कुछ स्लीपर सेल सक्रिय थे जो देशभर में काम रहे थे। इसी षड्यंत्र में इस बालिका का बलिदान हुआ। कालीबाई एक तेरह वर्षीय वनवासी बालिका थी। यह राजस्थान के इंगूरपुर जिले के वनांचल की रहने वाली थी। कालीबाई का जन्म कब हुआ, इसका इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता। अनुमानतः कालीबाई का जन्म जून 1934 माना गया। अंग्रेजीकाल में चर्च ने वनवासी अंचलों में अपने विद्यालय आरंभ करने का अभियान चलाया हुआ था, जिनका उद्देश्य वनवासी समाज को उनके मूल से दूर करना था। उनकी शिक्षा की शैली कुछ ऐसी थी कि वनवासी क्षेत्र में मतांतरण तेजी से होने लगा था। उस समय के अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और सामाजिक सांस्कृतिक संगठन इसके लिए चिंतित थे। विशेषकर ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो आर्यसमाज या राम-कृष्ण मिशन से जुड़े थे, उनमें यह भाव अधिक प्रबल था। राजस्थान में स्वामी दयानंद सरस्वती और

स्वामी विवेकानंद के बहुत प्रवास हुए थे, इसलिए राजस्थान क्षेत्र में इन दोनों संस्थाओं का प्रभाव था। सुप्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी नानाभाई खोटे आर्यसमाज से जुड़े थे। उन्होंने इंगूरपुर जिले के रास्तापाल गांव में एक विद्यालय आरंभ किया। विद्यालय में वनवासी बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया गया था। विद्यालय में उस समय की आधुनिक शिक्षा तो दी जाती थी, पर भारतीय गुरु शिष्य परंपरा को भी जीवंत किया था। विद्यालय ने शाम को एक प्रार्थना सभा का आरंभ भी किया, जिसमें वनवासी परिवार भी आने लगे। इस विद्यालय में मुख्य शिक्षक सेंगाभाई थे। वनवासी बालिका कालीबाई भी यहां पढ़ने आती थी। यह भील समाज से संबंधित थी। उसकी आयु अनुमानित तेरह वर्ष थी। यह क्षेत्र इंगूरपुर रियासत के अंतर्गत आता था। आर्यसमाज ने विद्यालय आरंभ करने की अनुमति महारावल इंगूरपुर से ले ली थी। इस क्षेत्र में एक चर्च भी सक्रिय था। इस विद्यालय और उसकी गतिविधि से वनवासी समाज चर्च से दूर होने लगा। चर्च को आपत्ति हुई। चर्च ने काश्मिरन को शिकायत की। अंग्रेजों ने भले भारत से जाने की घोषणा कर दी थी, पर उनकी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और रियासतों पर रूतबा कम न हुआ था। शिकायत मिलते ही कमिश्नर ने इंगूरपुर के महारावल पर दबाव बनाया और विद्यालय बंद करने के आदेश हो

गए। आदेश मिलते ही नानाभाई ने विद्यालय तो यथावत रखा और उन्होंने महाराज से मिलने का प्रयास किया, लेकिन अनुमति न मिली। मिलने का समय टाला गया। नानाभाई को आशा थी महाराज से मिलने के बाद अनुमति यथावत हो जाएगी, इसलिए विद्यालय बंद न हुआ। वे यह भी जानते थे कि अंग्रेज तो जाने वाले हैं। तब चर्च और अंग्रेज अधिकारियों के आगे क्यों झुकना। उनके इनकार करने से अधिकारी बौखला गए। भारी पुलिस बल के साथ अधिकारी विद्यालय पहुंचे। वे ताला लगाकर विद्यालय सील करना चाहते थे, किंतु शिक्षक सेंगाभाई ने विद्यालय के द्वार पर खड़े होकर रास्ता रोकना चाहा। पुलिस ने पकड़ कर किनारे किया और विद्यालय पर ताला लग दिया। शिक्षक सेंगाभाई को रस्सी से गाड़ी के पीछे बांध दिया गया। गाड़ी रवाना हुई तो शिक्षक सेंगाभाई घसीटते हुए जा रहे थे। उनका पूरा शरीर लहलुहान हो गया। रास्ते में कालीबाई खेत में काम कर रही थी। उसने देखा कि उनके गुरु को पुलिस गाड़ी में पीछे बांधकर घसीटते हुए लेकर जा रही है। कालीबाई के हाथ में हसिया था। वह हसिया लेकर दौड़ी और रस्सी काट दी। पुलिस इससे और बौखला गई। पुलिस ने गोशियां चला दी। पुलिस की गोली से कालीबाई का शरीर छननी हो गया। गोली की आवाज सुनकर भील समाज एकत्र हो गया।

वैश्विक हमलावर

डोनाल्ड ट्रंप अमनपसंद तो बिल्कुल नहीं हैं। सत्ता से बाहर रहने के दौरान उन्होंने अमेरिका के अनवरत चलने वाले युद्धों का विरोध किया था। उन्होंने दावा किया था कि अगर वे राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध कभी शुरू नहीं होता। ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिका के वैश्वकवादियों को उसके अनवरत चलने वाले युद्धों के लिए दोषी ठहराया था। फिर भी ट्रंप के कार्यकाल में वाशिंगटन के सबसे करीबी सहयोगी इजरायल ने 13 जून को ईरान पर उस वक्त हमला करना शुरू कर दिया, जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल ही रही थी। शुरू में तो ट्रंप और उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका इस जंग में शामिल नहीं है और उन्होंने ईरान को पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैनिकों या सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के खिलाफ चेताया। ईरान ने निशाना नहीं बनाया। तेहरान का जवाबी हमला पूरी तरह से आक्रमणकारी इजरायल पर केंद्रित था। लेकिन, एक हफ्ता बाद जब इजरायल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए जूझने लगा, तब अमेरिका के बी-2 बमवर्षक विमानों ने जहां ईरान के सबसे ज्यादा किलेबंद फोर्डो परमाणु संयंत्र पर बंकर-तोड़ बम गिराए, वहीं अमेरिकी पनडुब्बियों ने नतांज और इस्फहान परमाणु संयंत्रों पर टॉमहॉक मिसाइलें दागीं। इस प्रकार वह साफ तौर पर ट्रंप का युद्ध बन गया। वह शांति का वादा कर-के सत्ता में आए थे और मात्र छह महीनों में ही वह एक जंगबाज और वैश्विक हमलावर बन गए हैं। जहां तक जंग का सवाल है, तो अमेरिका ने अपनी गलतियों से शायद ही कुछ सीखा है। उसने 2001 में जब अफगानिस्तान पर हमला किया था, तो अलकायदा को मिटाने, तालिबान को हराने और उस देश को लोकतांत्रिक बनाने की कोशिशें कई थीं। लेकिन, 20 साल बाद उसने इस देश को तालिबान को वापस सौंप दिया। इसने 2003 में यह झूट बोलकर इराक पर हमला किया (और उसे तबाह कर दिया) कि बगदाद के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं।

Social Media Corner

सब के हक में...

गुप कैप्टन शुभांशु शुकला ने भारत के अंतरिक्ष में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है, पूरा देश एक भारतीय की सितारों की यात्रा पर उत्साहित और गर्वित है। वह और अमेरिका, पोलेंड और हंगरी के एक्सओ मिशन 4 के उनके साथी अंतरिक्ष यात्री साबित करते हैं कि दुनिया वास्तव में एक परिवार है- 'पसुधे कुटुम्बकम्'। इस मिशन की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं, जो नासा और इसरो के बीच स्थायी साझेदारी को दर्शाता है। चालक दल द्वारा किए जाने वाले व्यापक प्रयोग वैज्ञानिक अध्ययन और अंतरिक्ष अन्वेषण के नए आयाम स्थापित करेंगे। (राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का 'एक्स' पर पोस्ट)

कांग्रेस पार्टी पूरे देश में पिछले 1 साल से संविधान बचाओ आंदोलन चला रही है। इससे बीजेपी घबरा गई। जिनका देश की आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। जिनका संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा। जिन्होंने संविधान का विरोध किया- उसकी कौंपी जलाई, वो कांग्रेस पार्टी को संविधान के ऊपर नसीहत दे रहे हैं। मोदी सरकार अपनी सारी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए रोज नए कार्यक्रम और नारे देती है। फिफल विदेश नीति, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक बहाल, गरीब और अमीर की बढ़ती खाई, बंद उद्योगपतियों को नाजायज फायदा पहुंचाए जाने और बढ़ती सांघाधिकता जैसे मसलों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। इस समय देश में अधोषित आपातकाल है। न ये सरकार संविधान की रजत छत करती है और न संसद की।

(मल्लिकार्जुन खड़गे का 'एक्स' पर पोस्ट)

Three lessons for today from Emergency 1975

Come June 25, India will be observing the 50th anniversary of a murderous attack on its democracy. Announcing the cabinet decision last July, Home Minister Amit Shah had said that, as a reminder of how Indira Gandhi had thrown lakhs of people behind bars for no fault of their own and the way media’s voice was muzzled, the government had decided to observe every June 25 as ‘Samvidhaan Hatya Diwas’. He further stated, “This day will commemorate the massive contributions of all those who endured the inhuman pains of the 1975 Emergency.”

On March 21, 1977, India Gandhi decided to withdraw the Emergency after the results of that year’s Lok Sabha elections were announced. While the electoral verdict was the last nail on the coffin, many other factors hugely contributed to compel Mrs Gandhi to backtrack. One of them was the satyagraha movement started mainly by the RSS and Sangh-inspired organisations.

The RSS’s role in mobilising the satyagraha movement was appreciated by many, including by some who were diehard opponents of RSS ideology. Achyutrao Patwardhan, a noted socialist leader, is on record saying, “I am pleased to learn that the volunteers of the RSS, as well as any other group of political resistance, were willing to openly collaborate and support those who opposed Emergency and are able to work with enthusiasm and integrity, against the diabolical regime that resorts to blatant repression and lies.”

Deeply impressed by the satyagrahis’ valour in leading the movement in the face of police atrocities and brutality, CPI(M) leader A K Gopalan observed, “There must be some high ideal giving them indomitable courage for such a heroic act and sacrifice.” (June 9, 1979, Indian Express).The history of the Emergency, conducted in a draconian manner that independent India has never witnessed, has three key lessons that all Indians must learn. Firstly, the dynasty-driven political parties pose a serious threat to democracy. Remember, most dynastic parties emerged on the political horizon of India around the 1970s. It was in that decade that many dynasties tightened their stranglehold on otherwise ideology-driven parties and converted them into family businesses. There is reason to believe that Indira Gandhi’s brand of politics inspired them. By the late 1960s, Indira Gandhi realised that she was almost totally isolated in her party. Deeply disturbed by this, instead of re-building bridges, she chose to create her own party, only to realise that she could completely rely only on her close family members—especially her younger son Sanjay Gandhi. In the mid-1970s, with the opposition parties coming together and sharpening their attack, media roundly criticising her and anti-corruption youth movements in Gujarat and Bihar gaining momentum, a sense of insecurity overwhelmed Indira Gandhi’s mind. Alone at the top and suspicious of her colleagues in Congress—although it was completely under her control—she found dependable support in only in Sanjay. Her dependence was so complete that although she rescinded Sanjay’s directives on June 25, 1975 to cut power supply to media houses and keep high court chambers under lock, she couldn’t directly confront her son.

Over the years, the Indira-Sanjay duo became a model to orchestrate son-rises in different political parties. Remember, it is the post-Emergency era that has witnessed the emergence of younger generations among the Thackerays, Stalins, Abdullahs and the Yadavs of UP and Bihar coming forward to take control of the parties earlier helmed by their fathers. It would not be an exaggeration to suggest that the Emergency emboldened many to convert their parties into family fiefdoms. Dynastic parties do not just lack in ideology-based policy perspectives, but also promote birth-based discrimination, something that our Constitution rejects lock, stock and barrel.

50 years after Emergency, our democracy still fragile

The most important question for us today is — what have we learnt, what can we learn from the experience of the Emergency

REMEMBERING is somewhat easy, not forgetting much more difficult. Remembering involves recalling. In the case of the Emergency that was declared on June 25, 1975, just 50 years back, one can resurrect much of what happened in the following 21 months in considerable detail. The events are well chronicled and, above all, etched in the memory of those who lived through that period. The more challenging task is ‘not forgetting’, for it entails learning from that experience so that we are not “condemned to repeat” the same mistakes.

Hence, the most important question for us today is — what have we learnt, and even more importantly, what can we learn from the experience of the Emergency?

Looking back at those tumultuous months, perhaps the most important lesson for us is that there is a distinction between the letter of the law and the spirit of the law, and it is the latter that can nurture democratic life.

In 1975, the Allahabad High Court set aside Prime Minister Indira Gandhi’s Lok Sabha election victory on the grounds of electoral malpractices. Although the Supreme Court stayed that verdict, the opposition within the House and outside asked for her resignation on moral grounds. They questioned her moral legitimacy to rule and govern, invoking as it were, an appeal to the conscience (and not merely to the letter of the law) to do the right thing.

Mrs Gandhi prioritised political judgement over the moral one and we know the consequence of that decision. In the hustle and bustle of electoral competitive politics, the moral frequently loses out to the practical-political, and every time that happens democracy takes a step back. How can we bring the ‘moral’ back into political life?The Emergency has left us with this difficult question, and even today we are no closer to answering it. However, what that period in our history has shown is that democracy stays on track when governments take note of the concerns raised by the Opposition. When they dismiss them, as Mrs Gandhi did then, democracy is at risk.Our Constitution has provisions for declaring state and national emergency along with clauses for ‘preventive detention’. In fact, in 1975, the Emergency was declared under the existing constitutional provisions. The suspension of civil liberties and political rights, mass arrests of Opposition leaders, journalists and other dissenting voices under MISA (Maintenance of Internal Security Act) that allowed indefinite preventive detention, search and seizure without warrant, muzzling of the freedom of the press, postponement of elections to central and state legislative bodies, and with it, the concentration of power in the hands of the central executive, was made possible by the invocation of Article 352.This, more than anything else, has made us aware that our democracy is fragile and our rights vulnerable.



We cannot take either for granted. In 1975, even the Supreme Court ruled that writ petitions challenging the legality of detention could not be considered by the court during the period of the Emergency. Hence, without continuous vigilance by citizens and all institutions, we may always remain vulnerable.A few lessons have been learnt. In 1978, the 44th Amendment of the Constitution stipulated that Articles 20 and 21 (dealing with personal liberty) could not be suspended even during a declared Emergency. Since then, the Supreme Court has also made some course correction. Reflecting on its own (in)action during the Emergency, it has extended and strengthened the right to liberty. In 2017, a Constitutional Bench ruled that the right to life and liberty is inalienable and its limitation must be in accordance with a procedure that is fair, just and reasonable.All these important changes in the institutional framework are a product of ‘not forgetting’ the Emergency. However, much more still needs to be done. When legal scholars note that the rules for granting bail remain flexible, open to considerable interpretation, at times presuming guilt rather than innocence, then the task of protecting the citizen’s democratic rights remains unfinished and warrants urgent attention.No democracy is perfect. Each has its own weaknesses. In parliamentary democracies, elections often give one party the majority of the seats, and this allows it to shape laws and policies. Mrs Gandhi

advised the President to declare the Emergency without a formal meeting and endorsement by the full Cabinet, saying that the threat of internal disturbances warranted immediate action. In hindsight, we can only underline the need for strengthening processes of formal consultation in an environment where different points of view are likely to be expressed. It did not happen in 1975 and democracy got derailed.The Emergency did not merely suspend democratic rights. The policies during this period — from compulsory sterilisation to reporting dissent — were successfully and energetically pursued by innumerable officials at various levels. Writing about the extermination of Jews, Hannah Arendt argued that horrific acts of terror and violence were carried out by individuals who saw themselves as following orders. Bureaucratic structures promote this form of thoughtlessness and ‘banality of evil’.We could question that analysis and say that individuals always have a choice. When the Emergency was declared, some resigned from their positions and refused to endorse the government’s diktat. But expecting such heroic action from most people is unrealistic. Usually, the costs of critically assessing one’s actions, or the attraction of promised rewards, take their toll. These vulnerabilities can only be addressed by creating a system in which each institution is held responsible and accountable for its actions and individuals within them protected by norms of collective action.

New Olympics chief faces stiff challenge

The State must ban such labour practices and offer them dignified economic rehabilitation. Their dignity is their right, not a largesse bestowed by social privilege

Thomas Bach’s words summed up the importance of Kirsty Coventry’s position in the world of sport. “With her election, you (members) have also sent a powerful message to the world: the International Olympic Council continues to evolve,” declared the outgoing IOC president during the handover ceremony on June 23, which marks the birth of the modern Olympics. “As the first woman and first African to hold this position—and indeed the youngest IOC president since Pierre de Coubertin—she reflects the truly global nature and the youthful, forward looking spirit of our Olympic community.” Coventry is also the first to be elected from a developing country. In short, she made history the moment she took the key to the Olympic House in Lausanne from Bach.The transfer of the key is more than symbolic as it indicates that the two-time Olympic gold medallist from Zimbabwe now holds the most powerful position in all of sport. A lot is expected of her. During the last three months of the initiation period, she has shown glimpses of what is to come while saying she would prefer more consultation



among members and that she would prefer to listen first. Her first step towards that was a two-day ‘Pause and Reflect’ session with members. Yet, the world she is

walking into is more politically charged and divided than ever before. Amid persisting geopolitical tensions, Russian athletes are still not allowed to participate under their national flag. It needs to be seen how she and her team react to a world where global leaders are increasingly using sport to further their political ambitions. Then there is the Trump factor facing the sporting community, with two of the biggest events—the men’s football World Cup and the Olympics—to be held in the US in the next three years. Coventry will be directly associated with LA 2028’s organising committee. India would be looking towards Coventry with hope, especially with the country’s intention to host the 2036 Olympic Games. The Indian Olympic Association has sent the letter of intent and there has been buzz on the ground as well. Given the new IOC president’s roots in a developing country, India would be hoping for a closer association. The mental strength she exhibited while winning Olympic medals will be put to test again—this time as the IOC chief.

Protect data without hurting business

The blacklisting approach to regulating the cross-border flow of personal data can disrupt the operations of multinational companies in India. A key concern is that neither the DPDP Act of 2023 nor the draft rules of 2025 specify adequacy, standard contractual clauses, or binding corporate rules for such transfers

Under the Digital Personal Data Protection Act 2023 and its recently-released draft rules, personal data can be freely transferred to a foreign country and processed there as long as the country is not blacklisted by the Union government. The blacklisting approach is in contrast to the earlier approach of restricting data transfers only to a select list of countries.The current provisions have a direct impact on the multinational companies that process, store and collect personal data in multiple countries. For instance, if an MNC operating in India is located in a blacklisted country, then its operations would effectively cease under the DPDP Act. But it’s not clear what happens if it is located in a whitelisted country, but the data is transferred to one of its branches operating in a blacklisted country where it gets processed. The Act and the draft rules have not addressed this issue.Given that some amount of personal data is essential for providing goods and services, foreign companies operating in countries to which data transfers are prohibited (once notified by the government) may face challenges in conducting business in India. If data is already being transferred to a country that the government later restricts, immediate action would be required to halt such transfers. This gives rise to the question—is it desirable to put an outright ban on multinational organisations operating in blacklisted country without having a specific mechanism to regular cross-border transfer of data? The blacklist approach under the DPDP Act and the draft rules can backfire and harm businesses operating in India.

The Union government will issue the blacklist, based

on factors it considers relevant. However, there is no clarity on what these factors would be. Neither has an illustrative or comprehensive list of factors been mentioned in the Act or the draft rules nor has an obligation been imposed on the government to outline the mechanisms for regulating this list. This is necessary as greater transparency is needed to prevent arbitrary decision-making.

It is pertinent to note here that the DPDPA’s extraterritorial scope extends its applicability to data fiduciaries outside India, which means foreign companies collecting personal data of individuals in India must comply with the same. Cross-border data transfers will be allowed to all countries unless the government issues a notification prohibiting transfers to any specific country. Unlike privacy regulations around the world, the DPDP Act doesn’t specify particular mechanisms such as adequacy decisions, standard contractual clauses, or binding corporate rules for cross-border data transfers. It was anticipated that the government would clarify through the draft rules. But that has not happened. As such, the government’s decision to blacklist certain geographic locations for cross-border data transfer may be arbitrary, discretionary and discriminatory. There is also the possibility that India’s data localisation regime can land us in disputes before the World Trade Organization. Under the 1995 General Agreement on Trade in Services’ privacy framework, WTO members need to take a balanced approach when it comes to privacy rights and trade. Article XIV(c)(ii) of the agreement lays down that it should not prevent member states from adopting measures necessary

to ensure compliance with laws related to protecting individuals’ privacy in the transfer of personal data. Article IV specifies such measures should not lead to arbitrary or unjustifiable discrimination between countries. Therefore, India’s blacklisting strategy must not lead to



arbitrary or unjustifiable discrimination between countries.This is in contrast to the cross-border transfer of data under the European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR) that lays down a specific mechanism to facilitate cross-border transfer of data. Under the GDPR, cross-border data transfers are permitted only if adequate protection of personal data is ensured by the receiving organisation or country. As per Article 45 of the GDPR, cross-border transfers can take place provided they follow the corporate rules given in

Article 47 of the GDPR. Alternatively, there needs to be compliance with safeguards mentioned in Article 46 of the GDPR for the crossborder transfer to take place. These include standard data protection clauses, binding corporate rules, codes of conduct, certification mechanisms and ad hoc contractual clauses. The government should explore similar safeguards while regulating cross-border data transfers.Additionally, the transfer of cross-border data will have to take place in accordance with sector-specific laws. The DPDP Act stipulates that sector-specific laws will be given precedence. For instance, the IRDAI (Outsourcing of Activities by Indian Insurers) Regulations 2017 states that records pertaining to policyholders need to be confined to the Indian jurisdiction. This means even if the cross-border transfer of data is permitted for whitelisted countries, the IRDAI regulations will take precedence and cross-border transfer of policyholders’ data will not be permitted. This could pose potential obstacles when it comes to enforceability of the DPDP Act as sector-specific laws are ever-evolving and will thereby restrict the extent of cross-border transfer of data.

The restriction on transfer of cross-border data can have an adverse impact on India’s trade and business. The upcoming DPDP rules should address the above challenges to make it a robust legislation that achieves its objective of protecting personal data without harming India’s economic interests.

EPFO increases auto-settlement limit to Rs 5 lakh

New Delhi. The Employee provident fund officer (EPFO) has increased the auto-settlement limit for advance claims from existing Rs1 lakh to Rs 5 lakh, enabling members to receive higher funds in time of need. EPFO had first introduced auto-settlement of advance claims during the COVID-19 pandemic to provide quick financial assistance to members. Since then the facility has been extended to cover advance claims for illness, education, marriage, and housing purposes. These claims are processed automatically by the system without any human involvement, ensuring quick turnaround and transparency.

This step is part of EPFO's broader push to improve service delivery by using technology, said a labour ministry statement. With the elevated limit of Rs 5 lakhs, additional advance claims will now qualify for auto-settlement, leading to their processing within three days of submission. This enhanced limit and faster access to funds will help members get timely financial support when they need it the most.

In 2024-25, EPFO achieved a significant milestone by successfully processing a record 2.34 crore advance claims through auto-settlement, reflecting a sharp increase of 161% over the previous year. Around 59% of all advance claims in 2024-25 were settled through the auto mode. Continuing this upward trajectory, in the first two and a half months of FY 2025-26, EPFO has already auto-settled 76.52 lakh claims, constituting around 70% of all advance claims settled so far. This growth highlights EPFO's strong focus on automation and delivering faster, more efficient services to its members.

The labour ministry in a statement said that the move reaffirms the government's commitment to enhance ease of access for EPFO members. It said that the EPFO will continue to leverage technology and process simplification to ensure a seamless and efficient service experience. These reforms have not only accelerated the claim settlement process but have also contributed to minimising member grievances, further enhancing ease of living for the member.

Oil prices fall below \$70 as Trump announces ceasefire between Israel and Iran

New Delhi. Oil prices dropped below \$70 a barrel following US President Donald Trump's announcement of a ceasefire agreement between Israel and Iran. Global oil benchmark Brent Crude — which had surged more than 13% after the escalation between the two countries — was trading at \$67.89 a barrel, while WTI (West Texas Intermediate) was at \$65.05 a barrel as of 8:18 pm IST.

The 12-day-long conflict appeared to come to an end after Trump declared the ceasefire on Truth Social, describing it as “complete and total.” He stated that Iran would begin the ceasefire, followed by Israel twelve hours later, with a formal end to the conflict marked after 24 hours. “During each ceasefire phase, the other side will remain peaceful and respectful,” he added. However, Iran denied that any agreement had been reached, though it indicated a pause in military operations. “As of now, there is no 'agreement' on any ceasefire or cessation of military operations. However, provided that the Israeli regime stops its illegal aggression against the Iranian people no later than 4 am. Tehran time, we have no intention to continue our response afterwards,” said Iran's foreign minister Seyed Abbas Araghchi in a social media post. The conflict, which broke out on June 13, 2025, had caused oil prices to spike from around \$64-65 per barrel to \$74-75 per barrel due to fears of supply disruptions in the Middle East—responsible for roughly a third of global oil production. Although no major oil infrastructure was significantly damaged during the escalation, there were concerns about potential blockages of key maritime choke points—particularly the Strait of Hormuz, which handles about 20% of global crude and 25% of LNG (liquefied natural gas) shipments. The Strait is the main exit route from the Persian Gulf for oil exports from Saudi Arabia, the UAE, Kuwait, Qatar, Iraq, and Iran, and represents a large portion of the world's spare production capacity.

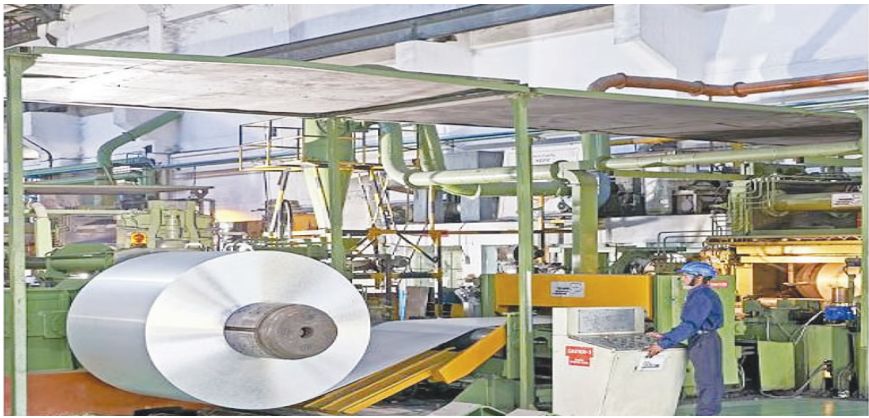
Personal Finance Advisor Reveals How India's New-Age Investors Are Reaping Rs 50 Lakh Profit In Real Estate

New Delhi. While most mutual fund investors are content with 12% CAGR over 10 years, some real estate investors subtly surpass 18-22% IRR by compounding hard assets, argues personal finance expert. "This is how India's new-age rich play the long game." These are the views expressed by Sujith SS, founder of the personal finance platform Moneydhan, in his LinkedIn post. Passive commercial incomeTo explain an investment idea, Sujith presented a financial case study and introduced Riya in his LinkedIn post. He says in the first year, Riya books two units for a new branded project launched in Gurgaon. "She's buying early due to price entry discount," he writes. Sujith says that at launch, the flat costs Rs 1.2 crore. Similar flats nearby are going for Rs 1.5 crore. That's a 20% discount. Riya books it with a staggered payment plan. "No EMI yet. No loan disbursement. Just early commitment," he writes. The tower is halfway up in year two, and the cost has slightly increased to Rs 1.4 crore. Demand is growing from NRIs and rental brokers. By year 3, as possession draws closer, the market value of her flat has increased to Rs 1.75 crore. Riya sells one unit and books a clean Rs 50 lakh gain. The other unit, she "Rent it out, earn 6% yield, and refinance against it at cheap rates," he writes. Sujith says that money from the sale of the flat is invested in a commercial unit. "Money that came after selling is invested into a pre-leased commercial unit near Nh8.

Hindalco to acquire US-based AluChem for \$125 mn

The acquisition will be carried out through Aditya Holdings LLC, a stepdown wholly owned subsidiary of Hindalco

New Delhi. Hindalco Industries Limited, the metals flagship of the Aditya Birla Group, has announced the acquisition of a 100% equity stake in US-based AluChem Companies, Inc., a prominent manufacturer of Specialty Alumina, for an enterprise value of \$125 million (around Rs 1,050 crore), the company said in a statement. The acquisition will be carried out through Aditya Holdings LLC, a stepdown wholly owned subsidiary of Hindalco. “This strategic acquisition marks a significant investment in specialty alumina, a key step in scaling its high-value, technology-led materials portfolio,” the company said on Tuesday. The transaction is expected to close in the



upcoming quarter, subject to customary closing conditions and regulatory approvals. The company said that Hindalco's Specialty Alumina business, a key pillar of its value-added strategy, has delivered consistent double-digit growth in recent years and emerged as a high-growth, high-margin vertical within the company's portfolio. As specialty alumina finds newer applications across cutting-edge sectors such as electric mobility, semiconductors, and precision ceramics, this acquisition, according to

the company, propels Hindalco up the innovation curve -- enabling access to next-generation alumina applications and driving value-accretive growth. “This acquisition is an important step in our global strategy to build a leadership position in value-added, high-tech materials. Our strategic foray into the specialty alumina space will not only accelerate the development of future-ready, sustainable solutions but also open new pathways to pursue high-impact growth opportunities,” said Kumar

Mangalam Birla, Chairman of Aditya Birla Group. He added that by integrating advanced technologies into our value chain, we are reinforcing our commitment to self-reliance, import substitution, and building scale in innovation-led businesses.

The global Specialty Alumina market is projected to grow significantly, with increasing demand for tailored solutions in sectors ranging from ceramics and electronics to aerospace and medical applications. Hindalco currently operates 500,000 tonnes of specialty alumina capacity and aims to scale up to 1 million tonnes by FY30. AluChem brings Hindalco a strong presence in North America with an annual capacity of 60,000 tonnes across its three advanced manufacturing facilities in Ohio and Arkansas. The company is a long-established supplier of ultra-low soda calcined and Tabular Alumina—materials known for their exceptional thermal and mechanical stability used in cutting-edge applications in high precision mechanical components, and energy-intensive industrial refractories.

Indian markets rise on easing geopolitical tensions and falling crude prices

BSE Sensex up 586 points of 0.73% to 82,641, while Nifty 50 gained 0.68% to 25,214.2.

CHENNAI. Wednesday (June 25) marked a broad risk-on session for Indian markets, supported by calmer geopolitical signals and lower crude prices. Benchmark indices, BSE Sensex rose 586 points of 0.73% to 82,641, while Nifty 50 gained 0.68% to 25,214.2. Gains were driven by relief from falling oil prices and optimism following a tentative ceasefire between Israel and Iran. All sectoral indices were in green territory, with meaningful contributions from IT, FMCG, mid/small caps, and select heavyweight stocks. Still, investors should remain watchful of stretched valuations, foreign outflows, and potential flare-ups in geopolitical tensions (notably around the Strait of Hormuz). Nifty MidCap +0.43%, Nifty SmallCap +1.36%. India VIX dropped nearly 3%, reflecting calmer market sentiment. Sectoral winners today were Nifty IT, up 1%, and Nifty FMCG, up 0.8%. The key drivers behind the rally include geopolitical ease, stable to

lower oil prices and stronger rupee. Ceasefire news boosted global risk sentiment and helped oil prices drop sharply—US futures saw West



Texas Intermediate fall of about 3.2% and Brent crude about 3.4%. Brent crude softened to sub-\$70 following the ceasefire—providing relief to India's import-heavy economy. The rupee strengthened 0.2% to ₹85.82/USD amid lower US yields, and RBI's liquidity withdrawal (₹1 trillion variable reverse repo auction) supported forward premiums. **Supply-Demand Imbalance in IPO**

Sensex has surged around 14% in six months, fueling a wave of IPOs (US\$1.75 billion expected this week) and secondary offerings amid stretched valuations.

Global Context
While MSCI World Index hit new highs, Asian and emerging market stocks reached their best levels since early 2022, and after Iran's missile strikes, Brent crude fell 7% intraday, with traders interpreting geopolitical signals as controlled and not targeting critical infrastructure. Iran's parliament voted to consider closing the Strait of Hormuz on June 22—a move carrying potential to disrupt oil flows, though deemed unlikely for now.

Risks & Caution Ahead
With Sensex up 14% over six months, record IPO/investment activity raises concerns of a bubble and potential correction if demand wanes. Similarly, any escalation in Middle East tensions may reignite oil price volatility.

No one from Adani Group charged under US FCPA: Gautam Adani

New Delhi. Adani Group chairman Gautam Adani on Tuesday stated that no one from the Group has been charged with violating the US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) or conspiring to obstruct justice. He made the remark during the group's annual general meeting (AGM). Adani, along with several senior executives, is under investigation in the US for allegedly orchestrating a \$265 million bribery scheme to secure solar energy contracts in India. According to the US Department of Justice (DOJ) and the Securities and Exchange Commission (SEC), between 2020 and 2024, Adani and his associates are alleged to have paid bribes to Indian officials in exchange for favorable energy deals. The authorities also allege that these actions were concealed from US investors during fundraising efforts. The allegations include potential

violations of the FCPA, as well as securities fraud and wire fraud. The Adani Group has strongly denied the accusations, calling them baseless. “We proved that true leadership is not built in sunshine but forged in the fire of crisis. This was tested again last year when we faced allegations from the U.S. Department of Justice relating to Adani Green Energy,” Adani said. “Despite all the noise, the fact is that no one from the Adani Group has been charged with violating the FCPA or conspiring to obstruct justice. We live in a world where negativity often echoes louder than the truth. As we continue to cooperate with legal processes, let me also reaffirm that our governance is of global standards, and our compliance frameworks are non-negotiable,” he added. During the AGM, Adani also highlighted the group's performance, stating that even

amid turbulence, the conglomerate recorded "record-breaking revenue, unprecedented growth, and historic profitability." Meanwhile, a Bloomberg report last month revealed that representatives of Adani have been in discreet talks with officials from the Trump-led U.S. administration. According to the report, the meetings began earlier this year and intensified in recent weeks, with Adani's emissaries arguing that the case conflicts with President Trump's current policy priorities. They are reportedly lobbying for the charges to be reconsidered or withdrawn. The developments come at a critical juncture for the Adani Group, which has been navigating regulatory and reputational challenges globally since a short-seller report last year triggered intense scrutiny of the conglomerate's financial practices.

India to roll out incentive scheme for rare earth production 15-20 days

Heavy Industries Minister H D Kumaraswamy said consultation with stakeholders is underway to decide the amount of the incentive programme. According to ministry officials, if the total incentive crosses Rs 1,000 crore, the scheme will be sent to the Union cabinet for approval

New Delhi. With the rare earth material supply crisis looming large, the government is set to launch an incentive programme to encourage domestic production of these minerals. The government will roll out a scheme to subsidise domestic production of rare earth magnets in 15-20 days, Heavy Industries Minister H D Kumaraswamy said on Tuesday. The minister said that consultation with stakeholders is underway to decide the amount of the incentive programme. According to ministry



officials, if the total incentive crosses Rs 1,000 crore, the scheme will be sent to the Union cabinet for approval. The latest crisis emanates from stricter controls imposed by China on the export of seven rare earth elements and finished magnets. This revised framework demands detailed end-use disclosures and client declarations, including confirmation that products will not be used in defense or re-exported to the US. This added scrutiny has prolonged the clearance process to at

least 45 days, leading to significant delays and a growing backlog that is tightening global supply chains. China is the world's dominant exporter of rare earth magnets, controlling over 70% of global Rare Earth Element (REE) production and over 90% of refining capacity. Kumaraswamy on Tuesday said India is looking at alternative sources for procurement of rare earth minerals in the interim period, including Japan and Vietnam. He informed that one Hyderabad-based

company has promised to deliver 500 tonnes by this year-end. The secretary said the actual production of rare earth magnets will take about two years, and the government, along with the industry, is looking at alternative sources of procurement in the interim period, including Japan and Vietnam.

Rare earth magnet, an alloy rare earth metal, are integral to Permanent Magnet Synchronous Motors (PMSMs), which are widely used in electric vehicles (EVs) for their high torque, energy efficiency, and compact size. Hybrid vehicles also rely on them for efficient propulsion. In Internal Combustion Engine (ICE) vehicles, their use is primarily limited to electric power steering and other motorized systems. Elements like Dysprosium (Dy), Terbium (Tb), Neodymium (Nd), and Praseodymium (Pr) are crucial for these magnets, especially in high-performance applications. Meanwhile, ministry officials said that said 30 automotive firms have sought authorisation from the Directorate General of Foreign Trade (DGFT) to import rare earth magnets from China a fortnight ago.

UAE Ambassador to India launches landmark start-up series to power cross-border innovation

Agency New Delhi.
New Delhi: The UAE-India CEPA Council (UICC), in partnership with the Embassy of the United Arab Emirates in India, launched the UAE-India CEPA Start-up Series at a high-level event hosted at the Taj Mahal Hotel, Delhi. The initiative delivers on a key commitment under the UAE-India Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) to promote innovation-led collaboration and support the internationalisation of Indian start-ups. In his special address, Abdunnasser Alshaali, PhD, the UAE Ambassador to India, underscored the UAE's commitment to entrepreneurship and cross-border innovation. "Start-ups are central to the UAE-India economic corridor. Through this Series, the UAE-India CEPA Council seeks to connect India's brightest entrepreneurial minds with the UAE's world-class ecosystem, supporting their scale-up journeys while enriching our bilateral innovation landscape," he said.

The launch comes amid a period of strong economic momentum between the UAE and India. In FY 2023-24, bilateral trade reached USD 83.64 billion, marking a nearly 15% year-on-year increase since the CEPA came into effect. India's non-oil exports to the UAE surged by over 20%, while UAE foreign direct investment (FDI) into India tripled, rising from USD 1.03 billion in FY 2021-22 to USD 3.35 billion in FY 2022-23, making the UAE India's fourth-largest investor. These gains further reinforce the UAE's enduring commitment to championing India's dynamic start-up ecosystem. Since 2000, UAE-based investors have channelled an estimated USD 20 billion into the Indian economy, fueling innovation, accelerating growth, and cementing the UAE's position as a key strategic partner.

Building on its efforts to deepen collaboration with India's innovation ecosystem, the launch event featured the signing of several Memoranda of Understanding (MoUs) between the

The event concluded with a presentation by Mr Ahmed Aljneibi, Director of the UICC, who unveiled the bold vision and strategic framework of the Start-up Series. He outlined how the initiative will culminate in a high-profile pitch event in New Delhi, where five exceptional start-ups will be selected to receive an exclusive UAE soft-landing package—including incubation support, business licencing, tailored mentorship, and direct access to leading investors, innovation hubs, and free zone networks across the Emirates. The event drew over 100 participants from across the start-up, investment, policy, and media landscape. Attendees witnessed the unveiling of the official Start-up Series microsite and the premiere of a promotional trailer calling for applications from high-potential Indian ventures.



UICC and prominent academic and entrepreneurial institutions, including PRIME Meghalaya under the Meghalaya Basin Management Agency (M.B.M.A.), IDEATE Lab @ O.P. Jindal Global University, and Jamia Hamdard.

India enters top 100 in UN's Sustainable Development Goals ranking

Agency New Delhi.
India has, for the first time, secured a place among the top 100 out of 167 countries ranked for their progress in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), according to a report published on Tuesday. According to the UN Sustainable Development Solutions Network's 10th and latest Sustainable Development Report (SDR), India ranks 99th on the 2025 SDG Index with a score of 67, while China ranks 49th with 74.4 and the US 44th with 75.2 points. India ranked 109th in 2024, 112th in 2023, 121st in 2022, 120th in 2021, 117th in 2020, 115th in 2019, 112th in 2018 and 116th in 2017. Among India's neighbours, Bhutan takes 74th place with 70.5 points, Nepal ranks 85th with 68.6, Bangladesh 114th with 63.9, and Pakistan 140th with 57 points. India's maritime neighbours, the Maldives and Sri Lanka, stood at 53rd and 93rd places, respectively. The SDGs were adopted in 2015 with the idea that to save the planet, no one should be left behind in the overall development matrix by 2030. The score measures progress on a scale of 0 to 100, where 100 indicates a country has achieved all 17 goals and 0 means no progress has been made.

The report's authors flagged that SDG progress has stalled at the global level, with only 17 per cent of the 17 targets projected to be achieved by 2030. "Conflicts, structural vulnerabilities and limited fiscal space impede SDG progress in many parts of the world," said the report, with world-renowned economist Jeffrey Sachs as its lead author. European countries, especially the Nordic nations, continue to top the SDG Index, with Finland ranking first, Sweden second and Denmark third. A total of 19 out of the top 20 countries are in Europe. Yet even these countries face significant challenges in achieving at least two goals, including those related to climate and biodiversity, largely due to unsustainable consumption, the authors said.

Man Wearing Burqa Enters Delhi Teen's Home, Pushes Her From 5th Floor

New Delhi. A 26-year-old man has been arrested for allegedly killing a 19-year-old woman by pushing her off the fifth-floor rooftop of her residence in northeast Delhi's Ashok Nagar. The accused, identified as Taufeeq, a resident of Rampur in Uttar Pradesh, was taken into custody late on Tuesday night after a brief period in hiding. The incident was first reported to the Jyoti Nagar Police Station around 8:30 am on Monday. According to the police, the victim,



Neha, was found in critical condition after being allegedly pushed from the rooftop of her family's residence. She was rushed to Guru Teg Bahadur (GTB) Hospital, where she died of her injuries later that day. To conceal his identity and avoid detection by the victim's family and neighbours, Taufeeq entered the residential building wearing a burqa. During interrogation after his arrest, Taufeeq admitted that he used the disguise to gain direct access to Neha without raising alarm. CCTV footage shows a figure in a burqa entering the building and later leaving under suspicious circumstances. Investigators are working to reconstruct the full timeline of events using footage from multiple cameras positioned around the complex.

Domestic air traffic rises 1.89% to 14.05 million in May, says DGCA

Agency New Delhi.
India's domestic air passenger traffic increased 1.89 per cent to 14.05 million in May compared to that of the same month last year, according to the Directorate General of Civil Aviation (DGCA). DGCA's monthly data showed the number of domestic passengers flown by Indian airlines in May 2024 was 13.79 million. In the previous month, IndiGo flew a total of 9.30 million passengers with a market share of



64 per cent, followed by the Air India Group, which recorded 3.72 million passengers, grabbing a 26.5 per cent market share. The two other major carriers, Akasa Air and SpiceJet, flew 0.74 million and 0.34 million passengers, respectively, during the month under review. Akasa's market share stood at 5.3 per cent, while SpiceJet's share in the total domestic passenger traffic was 2.4 per cent, as per the data. In terms of scheduled integrity, IndiGo delivered the highest on-time performance at 84 per cent in May, followed by Air India, which clocked 79.7 per cent OTP from six key airports, as per data. The six airports are Delhi, Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, Chennai, and Kolkata.

Rail Fares To Increase From July 1, Officials Say Lowest Hike In 12 Years

Agency New Delhi.
Train fares are set to increase marginally next month, Railway Ministry officials said. While the fare in non-AC class in Mail and Express trains will be hiked by 1 paise per km, tickets for travelling in AC classes will be dearer by 2 paise per km. "As compared to the previous fare revisions in 2020 and 2013, the current increase will be the lowest," a railway official told news agency PTI. "As far as suburban train and monthly season tickets are concerned, it has been decided not to increase any fare in the interest of daily commuters," the official added. The official said that second-class fare up to 500 km of travel will remain unchanged. For distances over 500



km, fares may be hiked by half paise per km. According to officials, train fare was last hiked on January 1, 2020. Then, second-class fare for ordinary and Mail/Express trains was increased by 1 paise/km and 2 paise/km, respectively. Fares in sleeper classes and all AC classes went up by 2 paise/km and 4 paise/km, respectively. "Before 2020, it was in 2013 when the train fares for all classes were revised significantly. For instance, the second-class fare for ordinary trains was raised by 2 paise and the second-class fare for Express/Mail trains increased by 4 paise. The sleeper class fare went up by 6 paise," the official said. "In 2013, all AC class fares, except AC II, were increased by 10 paise/km, and AC II fare went up by 6 paise/km." July will see another major change in Railways, as the ministry has decided to incorporate Aadhaar-based OTP authentication into the ticket reservation system to cut off middlemen.

Pak officer who captured Abhinandan Varthaman in 2019 killed in Taliban clash

Pakistani Major Moiz Abbas Shah, who was involved in the 2019 capture of Indian pilot Abhinandan Varthaman, was one of two personnel killed in a clash with Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) terrorists in the Khyber Pakhtunkhwa region.

Agency New Delhi.
Pakistani Major Moiz Abbas Shah, who was involved in the 2019 capture of Indian pilot Abhinandan Varthaman, was one of two personnel killed in a clash with Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) terrorists in the Khyber Pakhtunkhwa region. Security forces killed 11 terrorists, while two security personnel also lost their lives, during an intelligence-based operation (IBO) in the South Waziristan district of Pakistan, the military said in a statement on Tuesday. Following India's attack on a terrorist-training camp at Balakot in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa province on February 26 - twelve days after the Pulwama attack - Pakistan responded with a plan to target India's military installations. A fleet of up to 24 fighter



jets headed towards India, drawing a prompt response from India. An aerial dogfight ensued. Abhinandan Varthaman, then wing commander, was part of the Indian pushback team of Srinagar-based 51 Squadron. His plane, too, was shot down by Pakistan fighter jets. Abhinandan Varthaman ejected the plane to land on the other side of the

IAF to get at least 6 Tejas jets by March, delays due to engine unavailability: HAL chief

Agency New Delhi.
The Indian Air Force will get at least half-a-dozen Tejas Light Combat Aircraft by March 2026, Hindustan Aeronautics Ltd CMD D K Sunil has said, weeks after the IAF chief flagged serious concerns over delays in the delivery of the jets. Sunil, chairperson and managing director of the aviation behemoth, attributed the delivery delays to US defence major GE Aerospace missing the deadline for supply of its engines to power the fighter jets. The slippage in the delivery schedule for the LCA Mk-1A variant of the jet had become a major issue with Chief of Air Staff Air Chief Marshal A P Singh raising the matter publicly. Sunil said the delay was caused only due to the US firm's inability to supply the F404 engines on time. In an exclusive interview with PTI Videos, the HAL chief said GE Aerospace is expected to



supply 12 engines in the current fiscal. This will facilitate delivery of the jets to the IAF. "Every company goes through its fair share of criticisms. It does happen. Unfortunately, in the case of LCA Mark 1A, we have built the aircraft. As of today, we have six aircraft lined up," he said. "But the engine deliveries have not happened from GE Aerospace. They were to deliver the engines in 2023. Till date, we have got only one engine," he added. The delay from GE side was initially due

to production timelines falling behind during the Covid pandemic, and the subsequent departure of many senior engineers from the company, causing cascading supply chain bottlenecks. According to Sunil, the technical issues with GE Aerospace have been sorted out and HAL is set to receive 12 jet engines by March 2026. "I can assure you that as of today, six aircraft are ready. There is no let up from our side. We are building those aircraft and getting them ready and we will be in a position to deliver (by this fiscal)," he said. HAL plans to produce 16 jets in the coming year provided there is steady flow of engine supplies by GE Aerospace. In February 2021, the defence ministry sealed a Rs 48,000 crore deal with HAL for the procurement of 83 Tejas Mk-1A jets for the IAF. The ministry is also in the process of procuring 97 more LCA Mk-1As at a cost around Rs 67,000 crore.

Nitish Katara murder case: SC grants furlough to Sukhdev Pehalwan; orders security for Neelam Katara

The top court, earlier while hearing the matter pulled up the State and had issued a contempt notice to the Government of National Capital Territory of Delhi for its failure to comply with the directions of the court on taking decisions on remissions applications.

Agency New Delhi.
The Supreme Court on Wednesday (June 25) granted three-month furlough to Sukhdev Yadav alias Pehalwan who was awarded 20-year jail term in the Nitish Katara murder case. A bench comprising Justice Ujjal Bhuyan and Justice K Vinod Chandran granted the relief to Pehalwan on his plea challenging a Delhi High Court order dismissing his plea seeking his releasing on furlough for three weeks. The bench also directed authorities to provide security to Neelam Katara, the mother of Nitish Katara. The bench, while granting Pehalwan three-month furlough, noted that he has served 20-year uninterrupted jail term without remission and directed that he be produced before the trial court within a period of seven days and appropriate conditions be imposed on him by the trial court before grant of furlough. Yadav said in his plea that he had served the entire

sentence of 20 years as per the order of the court and the High court by refusing him to grant furlough failed to appreciate that he is entitled to avail furlough as he satisfies the eligibility conditions as laid down in Rule 1223 of Delhi Prison Rules, 2018. "The Hon'ble High Court all throughout has relied upon the judgement convicting the petitioner (Pehalwan) completely ignoring the fact that the offence in question dates back to the year 2002 and thereafter the petitioner has reformed himself which is reflected from his nominal roll that shows the jail conduct of the petitioner to be satisfactory, the condition necessary for being released on furlough," Pehalwan said in his plea. Pehalwan's plea seeking furlough was opposed by the State.

The top court, earlier while hearing the matter pulled up the State and had issued a contempt notice to the Government of National Capital Territory of Delhi for its failure to comply with the directions of the court on taking decisions on remissions applications. "We have seen in several cases concerning

the grant of remission that either the assurances given on behalf of the Delhi Government are not complied with or the orders of this Court are not complied with," the top court earlier observed. The apex court on October 3, 2016 awarded 25-year jail term without remission to Vikas Yadav and his cousin Vishal Yadav for their role in the Nitish Katara murder case and co-convict Pehalwan was awarded a 20-year jail term for his role in the case. They were convicted and sentenced for kidnapping Nitish Katara from a marriage party on the intervening night of February 16 and 17, 2002 and then killing him for his alleged affair with Bharti Yadav, sister of Vikas Yadav and daughter of Uttar Pradesh politician DP Yadav.



NEWS BOX

Canada beats El Salvador 2-0, advances to CONCACAF Gold Cup quarterfinals

HOUSTON. Jonathan David and Tajon Buchanan scored 2 minutes, 35 seconds apart early in the second half and Canada defeated El Salvador 2-0 on Tuesday night to reach the CONCACAF Gold Cup quarterfinals.El Salvador, which was eliminated, finished two men short after Santos Ortiz and Jairo Henriquez were ejected late in the first half.Canada won Group B with seven points and advanced to a quarterfinal against Guatemala on Sunday in Minneapolis, with the winner moving on to a semifinal against the U.S. or Costa Rica.

In the other quarterfinals, Mexico meets Saudi Arabia and Panama plays Honduras, both on Saturday in Glendale, Arizona.El Salvador was last in the group with one point, becoming the 14th team not to score a goal in the group stage.Canada coach Jesse Marsch returned from a two-game suspension assessed for his conduct during the CONCACAF Nations League third-place match against the U.S. in March.David



scored in the 53rd minute, his Canada record 35th goal in 66 appearances. He took a pass from Mathieu Choinière, turned and beat goalkeeper Mario González to the far post with a diagonal shot from about 15 yards.

González had jumped to his left to save David's penalty kick in first-half stoppage time after a foul by Jefferson Valladares on Jacob Shaffelburg.Buchanan scored his eighth goal in the 56th, lifting the ball over González after a feed from Niko Sigur, who had intercepted Diego Flores' pass

Ortiz received yellow cards in the 13th and 35th minutes, the second for a lunging tackle from behind on Sigur. Henriquez got a red card in the ninth minute of first-half stoppage time for elbowing Alistair Johnston in the head.Ortiz and Henriquez will be suspended when El Salvador starts the third round of World Cup qualifying in September.Honduras defeated Curaçao 2-1 at San Jose, California, on Luis Palma's goal in second-half stoppage time.Panama beat Jamaica 4-1 at Austin, Texas, behind Ismael Díaz's hat trick to win Group C with a 3-0 record, and the Reggae Boyz were eliminated in the group stage for the first time since 2009. Guatemala beat Guadeloupe 3-2 in Houston.

England chases down 371 runs to beat India in series opener at Headingley

LEEDS. England brilliantly paced a mammoth chase of 371 runs to beat India by five wickets and take the series-opening Headingley test on Tuesday with 14 overs to spare.England pulled off the 10th highest successful run chase in test history by playing clinically and confidently on a fifth-day pitch and in conditions, especially in the morning and afternoon, that suited India's bowlers.Ben Duckett's and Zak Crawley's magnificent opening partnership of 188 — knocking off more than half of the required runs — underpinned a chase that was ultimately finished in style by Jamie Smith's massive knee-down six over long-on.After a wicketless morning, pacers Prasidh Krishna and Shardul Thakur were India's surprising wicket-takers in the afternoon. When spinner Ravindra Jadeja claimed captain Ben Stokes after tea with 69 runs needed, the chase finally became tense.But Joe Root, 53 not



out, and Smith, 44 not out, removed all drama by hitting the remaining runs without giving India a sniff.The odds were heavily against England when it resumed the chase on a gloomy morning on 21-0, needing 350 more runs. But England strengthened its reputation for gunning down big targets. It achieved its 12th successful run chase in 14 chances at home under coach Brendon 'Baz' McCullum.In a big year for England with four more home tests against India followed by the Ashes in Australia, England said it was prioritizing winning over entertainment. And this wasn't a typical "Bazball" crash-bang chase, but grown up "Bazball," measured and controlled. The asking run rate was just under four an over and England stayed around it.

"What a mint test match," Stokes told the BBC. "To get to day five and come home with the win is amazing and what a game to be a part of. A great start to the series.

New Zealanders hail Auckland City's amateurs as 'heroic' after CWC draw with Boca Juniors

✎**Auckland lost 10-0 to Bayern Munich and 6-0 to Benfica in its first two matches, leading to questions over FIFA's decision to allow a team of part-timers to compete with the professional superstars of world soccer.**

WELLINGTON. It might not have been the shot heard around the world but it was a goal that reverbrated 13,000 kilometers (8,000 miles) away when Auckland City FC scored Tuesday to draw 1-1 with Boca Juniors at the FIFA Club World Cup.Christian Gray, a trainee teacher at Mt. Roskill Intermediate School in Auckland, rose to meet the corner of Jerson Lagos, a barber, and headed in the equalizer as the mostly-amateur team from New Zealand held Diego Maradona's fasmous old Argentine club to a draw.

Auckland lost 10-0 to Bayern Munich and 6-0 to Benfica in its first two matches, leading to questions over FIFA's decision to allow a team of part-timers from Oceania, it's

smallest confederation, to compete with the professional superstars of world soccer.

Even Auckland City's local paper, the New Zealand Herald, joined the critics, suggesting the team had "damaged Auckland City FC's proud 20-year legacy" in FIFA events."It's been a trying few weeks," the Herald reported after two defeats. "In the past, Auckland City have been renowned for punching above their weight on the global stage, while usually having a couple of outstanding individuals. That hasn't quite been the case here."But Auckland City left its best to last, producing an outstanding performance to the satisfaction of FIFA president Gianni Infantino, who was among the crowd at the match in Nashville.

"It's been a tough trip, you know, we've had some tough results but just happy for the team," Gray said. "I think we deserve it. We got a little bit of respect back I hope.We rely on volunteers, we don't have a lot of money so I'm just happy that they're happy."

The New Zealand media hasn't paid close attention to the Club World Cup, mostly focused on the end of the Super Rugby

competition. Soccer takes a back seat in rugby-mad New Zealand. But this result got prominent coverage.Radio New Zealand described the draw with Boca Juniors as "stunning.""Thanks to Gray's heroics and

probably impossible," the newspaper wrote. "But they have done it — against massive odds.Anyone around the football world coming across this result will be rubbing their eyes in disbelief. But it's true. It's all true."The Herald said Auckland City "will leave the tournament on a bit of a high, knowing that the painful journey has been worthwhile."A leading local news website, Stuff, said Auckland City "were rank outsiders against one of South America's most famous institutions.""Most of their team is comprised of amateur players who will be returning to their regular jobs at home. But they went toe to toe against one of South America's largest professional clubs that was home to Argentine icon Diego Maradona."Television New Zealand said Auckland City had been "humiliated" in its first two matches at the World Cup but their performance on Tuesday was "heroic."

It's unlikely a story of the same magnitude will be written in future. From now on Oceania — which includes the likes of New Zealand, Fiji and the Solomon Islands — will be represented by a professional team.



Liam Delap scores his 1st Chelsea goal in 3-0 win over Esperance in Club World Cup

✎**Chelsea finished with six points, one behind Group D leader Flamengo, and will play Benfica on Saturday at Charlotte, North Carolina, in the round of 16.**

PHILADELPHIA. Liam Delap scored his first goal for Chelsea and Enzo Fernández has two assists in a 3-0 win over Esperance on Tuesday night that helped clinch a round-of-16 berth in the Club World Cup.Tosin Adarabioyo scored on a header from 7 yards from Enzo Fernández's free kick in the third minute off first-half stoppage time. Delap scored two minutes later, taking Fernández's pass with his back to the goal, dribbling around Yassine Meriah and slotting it past goalkeeper Bechir Ben Said.

Tyrique George scored from the top of the circle seven minutes into second-half stoppage time on a shot that went in off the hands of Ben Said.A crowd of 32,967 attended the match at Lincoln Financial Field on a 90-degree night during a heat wave. There were hydration breaks in both



halves.

Key moment

Delap's goal was his first since the 22-year-old joined Chelsea from Ipswich just before the tournament.

Takeaways

Chelsea finished with six points, one behind Group D leader Flamengo, and will play Benfica on Saturday at Charlotte, North Carolina, in the round of 16. Esperance finished third in Group D and was

eliminated.

What they said

"Coming to this club of this size and getting my first goal means everything to me. Every goal is special, and this one is definitely up there." — Chelsea forward Liam Delap."We see that thepublic is always with us. Esperance fans are always present when we travel. There's great passion around the club." — Esperance midfielder Mohamed Wael Derbali.

Club World Cup: Benfica beats Bayern Munich in scorching heat to win Group C

CHARLOTTE. Andreas Schjelderup scored in the 13th minute to give Benfica a 1-0 victory over Bayern Munich in scorching heat on Tuesday, sending the Portuguese club to the top of Group C in the Club World Cup.The loss dropped Bayern Munich to second place as Boca Juniors was eliminated.The game was played in a 97 degree temperature (36 Celsius). Benfica winger Gianluca Prestianni was attended by the medical staff in the 25th minute due to heat-related issues and was replaced in the 55th.Schjelderup ran onto a cross from Fredrik Aursnes and scored with a right-footed shot from near the penalty spot.Bayern's Joshua Kimmich put the ball in the net in the 61st minute but the goal was disallowed because Harry Kane was in an offside position in the line of sight of



goalkeeper Anatoliy Trubin.

Bayern lost its first match of the tournament as it struggled to find a rhythm ahead of the knockout stages later this week, despite a late attacking effort including a disallowed goal.

Key moment

Schjelderup's early goal changed the

dynamic. Though insufficient, Bayern made an attacking effort that fell short against Benfica's organized defense, leaving the German champions unable to find an equalizer despite increased pressure in the second half.

Key stat

Bayern started only four of players from the starting lineup in Friday's win over Boca Juniors and introduced all five substitutes at the start of the second half: Kane, Kimmich, Konrad Laimer, Michael Olise and Jonathan Tah.

What they said

"Opponents play tough In the end when the goalkeeper is the man of the match, then you did not do everything wrong." — Thomas Müller of Bayern Munich."It's an important victory.



round value on English pitches that are no longer seaming as much."If Shardul Thakur is only going to bowl six to eight overs and not give you 15 overs in the day, there's no point in playing him," Panesar pointed out.Pressed on whether India should pick Kuldeep instead of Jadeja, Panesar didn't hesitate.I think they need to play Kuldeep because he has more of an X factor. There's something about him. Jadeja bowls too quickly. So I think, yeah, they need to bring in Kuldeep Yadav instead of Jadeja. He becomes the main attacking option," he said.But Panesar acknowledged India may hesitate to play only one spinner, especially given Jadeja's ability to contain runs.I just think India won't go with that.

We need to give them time: Gambhir on India's mis-firing pace attack

✎**Gambhir felt that Prasidh, who got five wickets in the match despite going for plenty of runs, has "all the ingredients of becoming a very good Test match bowler".**

LEEDS. The lack of depth in India's bowling resources was exposed during the opening Test defeat to England but head coach Gautam Gambhir has urged critics to give the inexperienced pace attack more time in its "early days".Barring Jasprit Bumrah, who got five wickets in England's first innings, none of the other bowlers looked penetrative as the hosts chased down a target of 371 with minimum fuss on the fifth and final day of the

match on Tuesday.The pace trio of Prasidh Krishna, Mohammed Siraj and Shardul Thakur was not consistent enough with the line and length."We will have to give them time. Earlier, we used to have four fast bowlers in the squad with an experience of more than 40 Tests. It doesn't make such a big impact in one-day or T20 matches, but when you go to Australia, England, or South Africa for Tests, experience matters," said Gambhir following the loss."These are early days. If we start judging our bowlers after every Test, how will we develop a bowling attack? Outside Bumrah and Siraj, we don't have that much experience, but they (the others) have quality, which is why they are in this dressing room."But we have got to keep backing them because it's not about one tour. It's about building a fast-bowler battery that can serve India for a long time in Test cricket."

Also part of the squad, Arshdeep Singh is yet to play a Test while Harshit Rana has featured in only two games.He felt that Prasidh, who

got five wickets in the match despite going for plenty of runs, has "all the ingredients of becoming a very good Test match bowler".

He also defended Shardul Thakur, who just



bowled 16 overs in the entire match with only six overs in the first innings."Sometimes captain goes with his instincts and Ravindra Jadeja gave us control in the first innings, that was important and we could rotate our three pacers at the other end," he said."We know what is Shardul's quality and that is why he is playing for India and is in the

dressing room. Just because he is the fourth seamer does not necessarily mean that he has to be brought ahead of a spinner. A captain went by his instinct and depending on surface, we were playing."Sometimes people fail: Gambhir on lower-orderTwo late batting collapses in as many innings cost India dearly in the series opener.

They were on course to amass 600 in their first innings but ended up with 471, losing seven wickets for 41 runs.In the second innings, the visitors lost six for 31 to allow England to come back in the game once again."First of all, I'll tell you it's not that they were not applying themselves," Gambhir said of the tail."Sometimes people fail, and that's okay. I know it is disappointing and more importantly, I think they are more disappointed than anyone. Because they knew that we had the opportunity. If we had got up to 570, 580 in the first innings, we could have dominated from there."It's not that they're not working hard in the nets as well.

Ankita Lokhande's Banter With Jannat Zubair

And Reem Shaikh Is All Things Fun

Ankita Lokhande has been winning hearts with her culinary art and hilarious punchlines in the cooking-based reality show, *Laughter Chefs: Unlimited Entertainment Season 2*. In the show, she is paired with her husband, Vicky Jain. As the season is about to conclude soon, the actress gave special marriage advice to her co-contestants Jannat Zubair and Reem Shaikh and it will surely leave you in stitches.

In a video shared by the makers on Instagram, Ankita is seen lip-syncing to the funny audio, "Zabaan chalaogi na shaadi nahi hogi tumhari fir (You won't get married if you speak too much)." Replying to this, Jannat and Reem, too, lip-synced to the audio, "Apki kaise hui fir (Then how did you got married)," leaving the actress breaking into mock tears and the viewers in splits. Sharing the clip, the makers wrote in the caption, "Shaadi ka laddu tasty ho yaa naa ho but *Laughter Chefs* mein entertainment ka dose toh ekdum perfect milta hai!" As soon as the makers dropped the clip, the comment section was flooded with



reactions from fans and admirers. An Instagram user wrote, "Jannat rocked Ankita. Shocked." Another one commented, "Ankita looking so beautiful." Some fans expressed their disappointment over the show going off air soon. One of them shared, "We'll miss this after some days."

Apart from the trio, *Laughter Chefs 2* also features an ensemble cast including Krushna Abhishek, Kashmera Shah, Abhishek Kumar, Samarth Jurel, Ali Goni, Rubina Dilaik, Rahul Vaidya, Sudesh Lehari, Nia Sharma, Karan Kundrra, Elvish Yadav and Vicky Jain. Notably, Mannara Chopra and Abdu Rozik were also a part of the show but left midway.

According to Siasat.com, Aly Goni and Reem Shaikh have emerged as the winners of this season of *Laughter Chefs 2*. The two joined the show midway and instantly became fans' favourites. Aly got the most Stars this season, demonstrating his culinary prowess and comedic timing.

The first runner-up spot has been secured by Karan Kundrra and Elvish Yadav, while Rubina Dilaik and Rahul Vaidya got the third spot, according to Siasat.com, citing insiders. However, the makers are yet to confirm the same.



Shruti Haasan's X Account Hacked? Actress Posts Bizarre Tweets About Memecoins



Actress and singer Shruti Haasan raised eyebrows on Monday, June 24, 2025, after a series of unusual tweets appeared on her official X (formerly known as Twitter) account. They were memecoins and cryptocurrency-related content. The sudden posts have led fans to speculate that her account may have been hacked. The tweets, which were entirely out of character and unrelated to the actress's usual content, included phrases like "Wait... @mcuban really dropped a memecoin? Just spotted it on @JaredDudley619, assistant coach of the Mavs."

It had vague mentions of cryptocurrency projects. None of the posts provided context or explanations.

While Shruti Haasan has not issued an official statement yet, many believe her account was compromised. Some fans even took to the comments to ask if her account was hacked. As of now, the questionable tweets remain on her timeline, and no clarification has been provided by her team or representatives.

Meanwhile, Shruti is gearing up for her next big-screen outing in the much-anticipated *Coolie*, directed by Lokesh Kanagaraj and starring the legendary Rajinikanth. The film is slated to release on August 14, and expectations are already running high.



When Alia Bhatt Admitted She 'Loved' Sidharth Malhotra: 'I'm Not Nachaoing Him...'



Alia Bhatt and Sidharth Malhotra shared undeniable on-screen chemistry when they debuted in *Student of the Year* (2012), the film that launched both their careers under Karan Johar. Their connection deepened during *Kapoor & Sons* (2016), and rumours of an off-screen romance emerged around the same time. Despite neither confirming it outright, they were often referred to as one of Bollywood's cutest pairs.

By 2017, their alleged one-year relationship ended, with Alia Bhatt later describing their split as mature and amicable. Before the breakup, Alia and Sidharth starred in *Kapoor & Sons* and during an interview with Rediff, she opened up on dating him. She had said, "I love him, there's no stress. I am not nachaoing (making him dance to my tune) him, in films or in real life."

Post break, she said, in a chat with DNA, "I have a lot of love and respect for Sidharth. I have known him for a long time and there's too much history between us. Honestly, there will never be issues. We have witnessed several milestones of our lives together. There are no bad vibes."

Sidharth echoed that sentiment during an appearance on *Koffee With Karan*, calling their breakup civil while talking about the shared history. "I don't think it's bitter. We haven't really met after that, to be honest. And it's civil. It's been a while and it happens... just like any other relationship. I have known her for much longer. I did know her much before, even before we were dating," he said.

Following the breakup, Alia and Sidharth distanced themselves personally, although they reconnected briefly at a Bollywood event in 2019, which Alia described as "extremely normal".

Both Alia and Sidharth have embraced married life wholeheartedly. Alia Bhatt found love with actor Ranbir Kapoor.

The couple got married in an intimate ceremony at their Mumbai home in April 2022. Later that same year, in November, Alia and Ranbir welcomed their first child, a daughter named Raha Kapoor. Meanwhile, Sidharth Malhotra married actress Kiara Advani in early 2023 in an intimate ceremony. They're now expecting their first child.



Jacqueline Fernandez Felicitated At Italian Global Series Festival, Calls It An Honour

While the buzz around *Housefull 5* continues, Jacqueline Fernandez has another reason to celebrate. This time, on the international stage. The actress was honoured at the 2025 edition of the Italian Global Series Festival (IGSF) in Rimini, where she was recognised for her contribution to cinema during the festival's grand opening night.

Sharing her joy online, Jacqueline posted photos from the prestigious event and penned a heartfelt message reflecting on the power of cinema. "Cinema as an art for me is not just about storytelling but a way to connect people across time, language, and continents. To be acknowledged for helping share that with the world means more than words can express! Grazie di cuore #IGSF2025 #ItalianGlobalSeriesFestival #Openingnight #TVseries #InEmiliaRomagna," she wrote.

The IGSF, known for celebrating excellence in both television and film on a global platform, saw Jacqueline among a select group of distinguished awardees this year. Being included in such company was clearly a moment of pride for the Kick actress, who added in her post, "@igsfestival it was an honour to be awarded here in Rimini at your prestigious event with all the extraordinary awardees in attendance. Here's to many more moments for us to celebrate cinema across the globe."

Professionally, Jacqueline has been keeping busy. She recently appeared in *Housefull 5*, a

comedy blockbuster directed by Tarun Mansukhani, which released on June 6, 2025. The film featured an ensemble cast including Akshay Kumar, Sanjay Dutt, Riteish Deshmukh, and more.

In addition, she also starred in the web series *Hai Junoon! Dream. Dare. Dominate*, directed by Abhishek Sharma, alongside Neil Nitin Mukesh and Boman Irani. Jacqueline



Fernandez is a Sri Lankan actress who has made a successful career in the Indian entertainment industry. She has also featured in music videos and appeared on various reality shows. Raised in Bahrain, Jacqueline later pursued a degree in mass communication at the University of Sydney. She began her professional journey as a television reporter in Sri Lanka before transitioning into the world of modelling. In 2006, she earned the title of Miss Universe Sri Lanka and went on to represent her country at the Miss Universe pageant the same year.